सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 113, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

जलता बांग्लादेश: कैसे बढ़ रही हैं भारत के लिए चुनौतियां ?

राजेश डोबरियाल

जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलनों ने सिर्फ़ शेख हसीना की सरकार को ही नहीं हटाया उन्होंने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया है जिस पर वह अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानीपूर्वक बढ़ रहा था। यह ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का। साल 2020 में बहुत से लोगों को यह जानकर झटका सा लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेज होने जा रही थी।

लेकिन जुलाई, 2024 में यह पूरी तरह से बदल गया। 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन के परिजनों को आरक्षण जारी रखने के बांग्लादेश हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ वह इस कदर बेपटरी हुआ कि बांग्लादेश पिछले डेढ़ साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। हालात कितने ख़राब हो चुके हैं यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक नेता के बयान से समझा जा सकता है जिनका कहना है कि देश में 'लोकतंत्र के बजाय 'भीड़तंत्र' क्यों आ गया?'

ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि यह सब कुछ हुआ कैसे और क्या स्थितियों के सुधरने की उम्मीद की जा सकती है? बीते गुरुवार को इंकलाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में और तनाव आ गया है। क्योंकि ये अफ़वाह उड़ी कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए हैं।

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं, 'शेख़ हसीना की सरकार के हटने के बाद से वहां अराजकता है। वहां बहुत टार्गेटेड हिंसा हुई है। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति और खराब हुई है।' हालांकि शेख़ हसीना के समय में भी जीडीपी बढ़ रही थी लेकिन वह आर्थिक विकास में तब्दील नहीं हो पा रही थी। अब वहां विदेशी निवेश में गिरावट आई है। जब अराजकता होगी तो आर्थिक प्रगति प्रभावित होगी ही।

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफ़ेसर हर्ष वी. पंत कहते हैं, 'भारत शुरू से ही कह रहा था कि अगर आपको शेख़ हसीना की सरकार को हटाना है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और हमें जो गुस्साई भीड़ दिखी थी पिछले साल बांग्लादेश की सड़कों पर उससे वह अभी तक उबर ही नहीं पाया है। पिछले डेढ़ साल में आर्थिक विकास, रोज़गार, यूथ मैनेजमेंट जैसे एक भी असल मुद्दे पर यूनुस सरकार ने क्या काम किया है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता।'

'प्रोफ़ेसर त्रिपाठी कहते हैं कि ऐसे लोग जो शेख हसीना के साथ नहीं थे और उम्मीद कर रहे थे कि वह जाएंगी तो फिर देश दूसरी तरफ़ बढ़ जाएगा वह निराश हो रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र में अगर आप संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं करवाते हैं और उसे भीड़ के हाथ में दे देते हैं तो फिर वही होता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। वैसे यह भारत के लिए बाद में बांग्लादेश के लिए पहले चिंता का विषय है। बांग्लादेश में भारत विरोधी एक गुट हमेशा से रहा है, लेकिन शेख हसीना के चलते वह प्रभावशाली नहीं हो पाया, अब वह प्रभाव की स्थिति में है। वही ताकतें अब प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई हैं। वहां अब जो हो रहा है उसमें तो सिर्फ़ बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, उसके लोगों की जिम्मेदारी है।'

प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, 'लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है आपको लगता है कि प्रगतिशील तबका वहां आकर वोट देगा? एक तरह से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो कट्टरपंथी गुट हैं उन्हीं को मुख्यधारा में जमाया जाए और उन्हीं को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। फरवरी में होने वाले चुनाव से कुछ बदलने की उम्मीद करना बेमानी है। बांग्लादेश में मुख्यधारा की दो पार्टियां हैं चरमपंथी उनके ख़िलाफ़ हैं। बीएनपी का तो शेख हसीना से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन उसे निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वह एक मुख्यधारा की पार्टी है और अब सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा है।'

लेकिन बीएनपी नेता के बयान को प्रोफ़ेसर त्रिपाठी पार्टी का सच्चाई का सामना होने की तरह देखते हैं। वह कहते है, 'बीएनपी को शुरू में लगा था कि शेख हसीना के जाने का फ़ायदा उन्हें होगा लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आरक्षण के ख़िलाफ़ जो आंदोलन था उसमें बीएनपी कहीं थी ही नहीं। बतौर राजनीतिक दल बीएनपी तो तितर-बितर हो गई है, 10 साल से चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो जिन लोगों ने पूरा आंदोलन किया और उस हद तक ले गए कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़े। उसमें मुख्य रूप से जमात-ए-इस्लामी और कुछ स्वतंत्र आवाज़ें थीं। इसलिए फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा और अब बीएनपी को यह दिख रहा है। पहले बांग्लादेश में एक तरह का दो-पार्टी वाला सिस्टम था लेकिन इस आंदोलन के बाद यह बदल गया है।'

प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं., 'आज बांग्लादेश की जो हालत है उसकी सबसे बड़ी वजह हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को यह कहकर लाया गया कि वह सब ठीक कर देंगे, पूरी तरह असफल हो गए। शायद वह यही चाह रहे हों कि चरमपंथी ही सत्ता में आएं।'

प्रोफ़ेसर त्रिपाठी कहते हैं, 'देखिए जो युवा नेता हादी की हत्या हुई उसमें यह कह दिया गया कि हत्यारे भारत भाग गए। यह तो आपकी विफलता है, आपकी पुलिस की, आपकी सुरक्षा एजेंसियों की, आपके सिस्टम की विफलता है कि कोई एक युवा नेता की हत्या की साज़िश रचता है, खुलेआम मार देता है और फिर आसानी से निकल जाता है। प्रोफ़ेसर त्रिपाठी भारत और बांग्लादेश के संबंधों के भविष्य को लेकर बहुत आशावान नहीं दिखते। वह कहते हैं, 'जब तक वह कुछ रचनात्मक नहीं कर पाते, अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं सुधार पाते तब तक वह राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारत का हौवा खड़ा करते रहेंगे। बांग्लादेश में अगर राजनीति में स्थायित्व आता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि भारत के साथ उनका बड़ा व्यापार है। लेकिन चूंकि वहां अराजकता है और ऐसे में आर्थिक विकास होना नहीं है इसलिए भारत को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, भारत विरोध वहां बना रहेगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत शायद ही दखल दे। यह बांग्लादेश के लोगों को ही तय करना है कि उन्हें प्रगतिशील रास्ते पर आगे बढ़ना है या कट्टरपंथ की राह पर।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भारत-न्यूज़ीलैंड के बीच फ्री ट्रेड समझौते पर मुहर

● कारोबारियों से लेकर किसानों तक को होगा फायदा

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन से फोन पर की बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच व्यापार का एक बड़ा समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बात की और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को अंतिम रूप देने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और साझा अवसर बढ़ेंगे। यह व्यापार समझौता मार्च 2025 में तब शुरू हुआ जब न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए थे। दोनों देशों ने इस समझौते को अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उम्मीद है कि यह समझौता आर्थिक जुड़ाव को काफी बढ़ाएगा, बाजारों तक पहुंच आसान करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। इससे नए आविष्कार करने वालों, कारोबारियों, किसानों, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कई सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे।

साथ ही छात्रों और युवाओं को भी नए मौके मिलेंगे। दोनों देशों के बीच जब यह समझौता लागू हो जाएगा तो न्यूज़ीलैंड को भारतीय सामानों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर तरह के सामान पर टैक्स खत्म हो जाएगा। यानी व्यापार टैरिफ फ्री रहेगा। यह समझौता किसानों, मजदूरों, कारीगरों, महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों और युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते जैसे ज्यादातर लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए भी नए मौके बनेंगे।

बंगाल में हुमायूं कबीर ने किया नई पार्टी का ऐलान

● दो सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जनता उन्नयन पार्टी होगा नाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी नई पार्टी का गठन किया है। इसका नाम उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी रखा है। बेलाडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कुछ उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें उनकी नई पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारेगी। भरतपुर के विधायक कबीर ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद की दो सीटों, रेजिनगर और बेलडांगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने पत्रकारों से कहा, यह पार्टी आम आदमी के लिए काम करने के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि वह आरएसएस के साथ मिलीभगत कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत के 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कबीर ने कहा कि वह भगवत का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां अशांति नहीं फैलेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

बड़वाह-धामनोद 4 लेन मार्ग के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख स्वीकृत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग मय पेव्हड शोल्डर (लंबाई 62.795 किमी) के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत भू-अर्जन सहित उन्नयन एवं निर्माण के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना अंतर्गत 10 बायपास, 5 वृहद पुल, 23 मध्यम पुल, 12 वीयूपी/एसवीयूपी 7 वृहद जंक्शन एवं 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा।

निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद् द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मापदण्ड के अनुक्रम में 16वां वित्त आयोग निर्धारित अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 में आगामी 05 वर्षों की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना में आंगनवाड़ी सेवा योजना (पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण सक्षम आंगनवाड़ी सहित), पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है। यह योजना प्रदेश के सभी 55 जिलों की 453 बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत 97 हजार 882 आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाती है।

मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रूपये की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव आवास तथा 12 मल्टीस्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण किया जाएगा। इस विधि विश्वविद्यालय में (बीएएलएलबी (एचओएनएस) एलएलबी (एनओएनएस) एवं पीएचडी पाठ्यक्रम में 1,272 सीट्स स्वीकृत हैं।

राजस्थान में अरावली पर्वत को बचाने के लिए आंदोलन

● जोधपुर में लाठीचार्ज, कई शहरों में पुलिस-प्रदर्शनकारी भिड़े

सीकर (एजेंसी)। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के लोगों की उदयपुर कलेक्ट्रेट में पुलिस से धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया। सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान बेरिकेड्स पर चढ़ गए।

शरद की सुबह

नब्बे पार में भी
हमें
युवा बने रहना है

नब्बे पार में भी
हमें
सिर ताने रखना है

नब्बे पार में भी
हमें
फूलों-सा महकते
रहना है

नब्बे पार में भी
हमें
प्यार की नदी में
तैरते रहना है

नब्बे पार में भी
हमें
अपने हृदय की धरती को
सुगंधित बनाये
रखना है।

-दुर्गाप्रसाद झाला

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से अभी और गिरेगा पारा

● देश में मौसम का सितम, ठंड से कांपा उत्तर भारत ● रेल और हवाई यातायात प्रभावित, कड़ाके की ठंड

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बूंदाबांदी के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते रहे तो रेल यातायात के साथ विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। धुंध के कारण श्री माता वैष्णो देवी में कटड़ा-सांझीछत चापर सेवा प्रभावित हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद लगातार चार दिन तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी। दिल्ली के लिए ठंड और कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल तो पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.2 और 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में चार दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं हैं। राज्य के सात शहरों में कोहरा छाया रहेगा तो 25 जिलों में ज्यादा ठंड रहेगी। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के साथ 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत हुई। विख्यात पर्यटन स्थल सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित कश्मीर के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है।

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

देश के 68 करोड़ यूजर के ई-मेल और पासवर्ड लीक

मध्य प्रदेश स्टेट साइबर ने जारी की एडवाइजरी, कहा-तुरंत रीसेट करें पासवर्ड

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की है। जिसमें बताया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ई-मेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने का मामला सामने आया है। एडवाइजरी में कहा है कि ई-मेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य एप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट करें। स्टेट साइबर पुलिस के मुताबिक चेतावनी डेटा लीक और साइबर ठगी के खतरे को देखते हुए पहले से सतर्क करने की पहल है। समय रहते पासवर्ड बदलना, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना और अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग पासवर्ड रखना सबसे प्रभावी बचाव है। स्टेट साइबर एसपी प्रणय नागवंशी ने बताया कि देशभर में 68 करोड़ इंटरनेट यूजर के ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास होने का अनुमान है। प्रत्येक वेबसाइट या ऐप के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखने चाहिए। संदिग्ध ईमेल, एसएमएस, लिंक पर क्लिक न करें। अनजान ऐप

या वेबसाइट पर लॉग इन न करें। नागवंशी ने कहा- हमने यह एडवाइजरी इसलिए जारी की है, क्योंकि कई लोगों का डेटा कहीं न कहीं डार्क या डीप वेब पर लीक होता रहता है। इसी को देखते हुए सभी से अपील है कि वे समय-समय पर अपने ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड जांचते रहें और उन्हें बदलते रहें। साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, मजबूत अल्फा-न्यूमेरिक पासवर्ड बनाएं और किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। ई-मेल आईडी में टू-फैक्टर वेरिफिकेशन के चालू होने से अगर हैकर के पास आपकी मेल आईडी का पासवर्ड भी होगा, तब भी वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि आईडी का पासवर्ड डालने के बाद टू-फैक्टर वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जो केवल आपको ही पता होगा, इससे हैकर आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। टू-फैक्टर वेरिफिकेशन में भी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर ई-मेल की परमिशन मांगी जाती है, तब आपको सावधानी बरतते हुए ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपने क्लिक कर दिया, तो सभी जानकारी हैकर के पास चली जाएगी। अगर आप गलती से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तब आप तुरंत ही अपना पासवर्ड बदल लें. इससे फिर एक बार ई-मेल आईडी का एक्सेस आपके हाथ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर एसपी प्रणय नागवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में 68 करोड़ इंटरनेट यूजर के ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास होने का अनुमान है।

मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने से गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मनरेगा के खत्म होने को सामूहिक नाकामी बताया और इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की है। सोनिया गांधी का यह बयान तब आया है, जब

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल को मंजूरी दे दी है, जो मनरेगा की जगह लेगा। इस नए कानून में ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम देने की गारंटी दी गई है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने कॉलम द बुलडोजर डिमॉलिश ऑफ मनरेगा में यह बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार गलत कर रही।

आसमान में था विमान, हवा में बंद हुआ एक इंजन

355 यात्रियों की सांसत में आई जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से उड़ान भरकर मुंबई जा रहा एयर इंडिया का वह विमान करीब एक घंटे का सफर कर चुका था। 355 यात्रियों के साथ आसमान को छू रहे विमान में अचानक ऐसी गड़बड़ी का पता चला कि इसे तुरंत वापस दिल्ली की ओर मोड़ना पड़ा। विमान को दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतार लिए जाने के बाद ही राहत की सांस ली जा सकी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक, क्रू मेंबर को दाहिने इंजन में लो ऑइल प्रेशर का पता चलने पर विमान को तुरंत वापस मोड़ा गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,22 दिसंबर को एआई 887 दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के क्रू ने एक तकनीकी दिक्कत के बाद एसओपी के तहत तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला किया। बयान में इस बात का ब्योरा नहीं दिया गया कि किस तरह की गड़बड़ी का पता चला था।

नागर विमानन मंत्रालय ने लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने टेक-ऑफ के तुरंत बाद तकनीकी समस्या से जुड़ी एयर इंडिया की उड़ान एआई-887 की घटना का संज्ञान लिया है। पोस्ट में कहा गया कि मंत्रालय ने एयर इंडिया से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और डीजीसीए को इस मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइन को नोटिस जारी किया है।

इंजन ऑइल का प्रेशर जीरो हो गया था

डीजीसीए ने इस घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि एयर इंडिया के विमान ने एयर टर्नबैक क्योंकि टेक-ऑफ के बाद फ्लैप्स समेटते समय फ्लाइट क्रू ने इंजन नंबर-2 (दाहिने इंजन) में इंजन ऑइल प्रेशर कम पाया। कुछ देर बाद इंजन में तेल का प्रेशर जीरो हो गया। डीजीसीए ने कहा कि प्रोसीजर का पालन करते हुए क्रू ने इंजन नंबर-2 बंद कर दिया और एयरक्राफ्ट दिल्ली में सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ। विमानन नियामक ने कहा कि विमान की जांच चल रही है। डीजीसीए ने कहा कि डायरेक्टर एयर सेफ्टी की देखरेख में विमान कंपनी के परमानेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की ओर से जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से सौजन्य मुलाकात

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली के बिहार निवास में नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा नितिन नबीन से सौजन्य मुलाकात कर उनको बधाई दी। मुलाकात के बाद डॉ. मोहन यादव ने बताया की नई पौध को प्रयास करके आगे लाना सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व में सबसे युवा देश है और पूरे विश्व में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। यह सब बाबा महाकाल की कृपा है। मध्यप्रदेश गरीब महिलाओं और युवाओं के साथ हमेशा खड़ा है और आगे बढ़ रहा है।

भोपाल के आर्च ब्रिज पर चढ़ा युवक

पुलिस और नगर निगम की टीम ने घंटे की मशक्कत के बाद उतारा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बड़े तालाब पर बने आर्च ब्रिज पर करीब 50 फीट की ऊंचाई तक युवक अर्ध नग्न होकर चढ़ गया। वह ब्रिज से तालाब में छलांग लगाने की धमकी दे रहा था। हालांकि उसकी कोई मांग नहीं थी।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने युवक को समझाइश देकर नीचे उतार लिया। तलैया थाने के टीआई दीपक ढहरिया ने बताया कि दोपहर करीब 1:15 बजे युवक ब्रिज पर चढ़ गया था।

जिसकी सूचना डायल 112 पर राहगीरों ने दी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नगर निगम की टीम की मदद से युवक को समझाइश देकर उतार लिया। वह मानसिक विक्षिप्त था।

वहीं नगर निगम के गोताराखोर शेख आसिफ ने बताया कि युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा है। वह तालाब में कूदकर सुसाइड की धमकी दे रहा था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। युवक कमला पार्क और पास के इलाकों में अकसर भीख मांगता दिखाई दिया है।

एक गोत्र होने पर शादी से इनकार ,टॉवर पर चढ़ी युवती

खातेगांव (देवास) (नप्र)। देवास में प्रेमी से शादी करने की जिद में नाबालिग लड़की 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। मामला रविवार का सतवास तहसील के धासड़ गांव का है। इसका वीडियो सोमवार को सामने आया है। लड़की को टॉवर पर चढ़ा देखकर गांव वाले घबरा गए। उन्होंने पुलिस की डायल 112 पर सूचना दी। कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई। गांव वाले लड़की को समझाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों के मुताबिक लड़की टॉवर पर चढ़ने के बाद राहुल नाम के युवक और परिजनों को बुलाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि मुझे राहुल से ही शादी करनी है, परिवार नहीं मान रहा है। इससे वह परेशान है। लड़की का कहना था कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगी। बताया जा रहा है कि युवक और लड़की का गोत्र एक है, इसलिए परिजन रिश्ते के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर घर में विवाद चल रहा था। टॉवर पर चढ़ने के बाद लड़की ने नीचे उतरने से मना कर दिया। यह घटनाक्रम करीब डेढ़ घंटे तक चला। जब कुछ ग्रामीण उसे समझाने के लिए टॉवर पर चढ़ने लगे तो लड़की ने वहां से छलांग लगा देने की धमकी दे दी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई।

बिहार के मुंगेर में होगा रेल वैगनों का निर्माण

पटना (एजेंसी)। बिहार में रेलवे की सामग्री का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण कारखाने जमालपुर वर्कशॉप को अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कारखाने में अब रक्षा सामग्री की ढुलाई करने वाले वैगनों का निर्माण किया जाएगा। यह इस कारखाने

के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कारखाने में अब ऐसे खास वैगन भी बनाए जाएंगे जो भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारी-भरकम रक्षा उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। एशिया के पहले रेलवे कारखाने जमालपुर वर्कशॉप में अभी पेट्रोलियम और इसी तरह के अन्य तरल पदार्थों के परिवहन वाले क्रेन का निर्माण किया जाता है।

देश में दो नमूने, एक दिल्ली, दूसरा लखनऊ में

● योगी ने कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव को खूब सुनाया

अखिलेश बोले-यह आत्मस्वीकृति, खींचतान चौराहे पर न लाएं

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का सोमवार को दूसरा दिन था। प्रश्न काल के दौरान सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में सपा के आरोपों पर कहा- प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। एक कहावत है- चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने नाम लिए बिना कहा-देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर चले

हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बउआ के साथ भी होता है। वह फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहां चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान के 40 मिनट बाद ही अखिलेश ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा- आत्म-स्वीकृति... किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें।

● कफ सिरप पर चर्चा की मांग पर वेल में आए सपा विधायक- इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने कोडीन सिरप कांड पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मंजूरी नहीं मिली तो विधायक भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- कोडीन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा- सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो जरूर चर्चा कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा- अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।

बांग्लादेश में हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला

घर में घुसकर गोली मारी,कान के आर-पार निकली

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलना में सोमवार दोपहर 12 बजे नेशनल सिटिजन्स पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब शिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने सीधे मोतालेब के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर खुलना मेडिकल

कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में उनकी हालत काफी नाजुक थी। डॉक्टरों ने बताया कि गोली कान के आर पार निकल गई। पुलिस अधिकारी अनिमेष मंडल ने कहा कि गनीमत रही कि गोली दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे उनकी जान बच गई। मोतालेब शिकदर एनसीपी के खुलना डिवीजन के प्रमुख हैं और पार्टी से जुड़े मजदूर संगठन श्रमिक शक्ति के आयोजक भी हैं।

फरवरी से बदल जाएगा महंगाई-जीडीपी मापने का तरीका

● मोदी सरकार नई सीरीज जारी करेगी ● अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर होती है कैलकुलेट

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई और देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज (नए बेस ईयर) के साथ जारी किए जाएंगे। वहीं मई 2026 से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े भी नई सीरीज में जारी होंगे। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभी जीडीपी और रिटेल महंगाई के आंकड़े पुराने आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। जबकि दुनिया के कई देशों में ये हर 5 साल में अपडेट होता है। बेस ईयर में इस बदलाव का मुख्य मकसद डेटा को मौजूदा दौर की जरूरतों और खपत के हिसाब से ज्यादा सटीक बनाना है।

फिलहाल देश में महंगाई और जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए पुराना बेस ईयर (आधार वर्ष) इस्तेमाल किया जा रहा है। लंबे समय से एक्सपर्ट्स यह मांग कर रहे थे कि आधार वर्ष को अपडेट किया जाए।

खाने-पीने की चीजों का वेटेज कम होगा

अभी रिटेल महंगाई के कैलकुलेशन में फूड आइटम्स यानी खाद्य पदार्थों का हिस्सा काफी ज्यादा है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नई सीरीज में खाने-पीने की चीजों के वेटेज को कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है, वे खाने के बजाय दूसरी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नई सीरीज में इन आधुनिक जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन , जो देश के मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की रफ्तार बताता है। उसे मई 2026 से नई सीरीज में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें उन नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा, जिनका उत्पादन हाल के वर्षों में शुरू हुआ है। जबकि उन पुराने सामानों को लिस्ट से हटाया जा सकता है, जिनकी अब बाजार में मांग नहीं रही। सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने पहले भी संकेत दिए थे कि डेटा में सुधार की प्रोसेस चल रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में पुराने मानकों पर डेटा जारी करने से कई बार पॉलिसी बनाने में दिक्कत आती है। नया बेस ईयर आने से बैंक को भी ब्याज दरों पर फैसला लेना होगा।

भारत के साथ टू फ्रंट वार की तैयारी ! सऊदी जैसा समझौता !

पाकिस्तान और बांग्लादेश तैयार कर रहे सीक्रेट रक्षा समझौता

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान और बांग्लादेश जल्दी ही एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता कर सकते हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई

दिशा देने में अहम होगा। फिलहाल दोनों पक्ष मिलकर इसका खाका तैयार करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंसी और सेना के अधिकारियों के हालिया महीनों में किए गए ढाका दौरों के बाद ये खबर सामने आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौता पूरे क्षेत्र और खासतौर से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक टॉप सूत्र के हवाले से बताया है कि इस्लामाबाद और ढाका ने एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया है। प्रस्तावित समझौते की सामग्री और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है। यह पहल दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और रणनीतिक समन्वय के लिए है। रिपोर्ट में सीनियर डिप्लोमैटिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है।

● भारत को घेरने की तैयारी, यूनुस-शरीफ आए साथ- हाल के महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने लगातार एक-दूसरे के देशों को दौरे किए हैं। दोनों देशों की सेना, वायु सेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस साल कई बैठकें की हैं। कई सैन्य समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। ढाका में बीते साल अगस्त में यूनुस के सत्ता संभालने के बाद इस सिलसिले में तेजी आई है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना और एजेंसियों की बढ़ती दखल ने भारत की चिंता बढ़ाई है।

स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने एवं ड्रॉपआउट दर को घटाने के लिये किये गये ठोस प्रयास : सिंह

बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, शैक्षणिक सत्र समय पर कराई गई उपलब्ध

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि इस वर्ष शैक्षणिक सत्र में बच्चों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली बार 'प्रवेशोत्सव' का आयोजन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही शुरू किया था। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सराहनीय रही है। स्कूलों में कक्षा एक, 6 और 9 में प्रवेश प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिये प्रधानाध्यापक और माध्यमिक शाला में कक्षा 9 में प्रवेश के लिये प्राचार्य को जिम्मेदारी दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह सोमवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में विकास और सेवा के 2 वर्ष पर केन्द्रित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल, परिवहन विभाग के सचिव श्री मनीष सिंह, परिवहन आयुक्त श्री विवेक शर्मा, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह एवं विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय उपलब्धि

● प्रदेश में 80 प्रतिशत नियमित शिक्षकों की एवं 96 प्रतिशत अतिथि शिक्षकों की 'हमारे शिक्षक' जियो टेग आधारित ऐप में दर्ज की जा रही है। इस ऐप में अवकाश प्रबंधन और शिकायत निवारण सुविधा भी 1 जनवरी 2026 से लागु कर दी जायेगी। ● 18 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास। ● आगामी शैक्षणिक वर्ष से पूर्णतः ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन एवं प्रवेश के लिये सॉफ्टवेयर। ● पहली बार जिलों को सरकारी स्कूल भवन मरम्मत, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था के लिये निधि आवंटित। ● अगले वर्ष तक सभी सरकारी हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं मिडिल स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था। ● प्रदेश के 275 सांदीपनि एवं 799 पीएमश्री विद्यालयों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित करने की योजना।

प्रोत्साहन एवं अन्य योजनाएं- स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई गईं और उनकी छपाई गुणवत्ता में सुधार किया गया। 94 हजार 300 प्रतिभाशाली बच्चों को लेपटॉप और 7 हजार 800 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। पहली बार साइकिल वितरण का कार्य अगस्त माह में ही कर लिया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र से अप्रैल 2026 में ही साइकिल वितरण का कार्य किया जायेगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, छात्रावास एवं छात्राओं के सेनिटेशन एवं हाइजीन के लिये डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान की तीसरी किश्त के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने वाला देश का तीसरा एवं पहला बड़ा राज्य मध्यप्रदेश है। प्रदेश में पहली बार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था 1 जुलाई को पूर्ण की गई। वर्तमान में 76 हजार 325 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। सरकारी स्कूलों में 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण, शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में किया गया। सरकारी स्कूलों में 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजा गया।

कक्षा 5 एवं 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणाम मार्च में घोषित

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि कक्षा एक में कुल नामांकन वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में 19.6 प्रतिशत एवं शासकीय विद्यालयों में 32.4 प्रतिशत अधिक रहा है। प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हो, इसके लिये कक्षा 5 एवं 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम मार्च माह में ही घोषित कर दिये गये। उन्होंने बताया कि शासकीय योजनान्तर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र परिवारों के लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति पूर्णतः ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की गई। पिछले 3 वर्षों में सभी कक्षाओं में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 6.8 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई है। समग्र आईडी के माध्यम से 90 प्रतिशत बच्चों की ट्रेकिंग पूर्ण की गई है।

परिवहन विभाग की उपलब्धियां

परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकार वार्ता में परिवहन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि सेवाओं को पोर्टल 'वाहन तथा सारथी' के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में विभाग की समस्त सेवाओं को फेसलेस रूप में प्रदान करने वाला मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य बन गया है। परिवहन विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की सहायता देने के लिये एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी मान्यता प्रदान की गई है। नागरिक प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक सेवा केन्द्रों से परिवहन की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

मुख्य उपलब्धियां

- यात्री बसों के परमिट जारी करने में आ रही समस्याओं के लिये संभागीय आयुक्त राजस्व की अध्यक्षता में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये मोटरयान कर में पूर्ण छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान।
- सीएनजी वाहनों पर कर में 1 प्रतिशत की छूट।
- पुराने वाहनों को स्क्रेप कराने के बदले क्रय किये जाने वाले नवीन वाहन पर 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान।
- प्रादेशिक, संभागीय और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय।
- वाहनों की मानव हस्तक्षेप रहित पारदर्शी तरीके से फिटनेस जाँच किये जाने के लिये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन एवं देवास जिलों में 16 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का संचालन।
- वर्तमान में सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत निजी बस ऑपरेटर निर्धारित रूट में समय-सारणी की अनुज्ञा प्राप्त कर सार्वजनिक परिवहन बसों का संचालन कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग परिवहन विभाग के अधिकारी एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है।
- मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी की स्थापना। बस स्कीम के माध्यम से प्रथम चरण में इंदौर शहर के 50-60 किलोमीटर की परिधि में रूटों की पहचान कर अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया जारी।
- प्रदेश की सभी बसों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित।

ऊर्जा मंत्री बोले- बिजली चोरी रोकने विद्युत थाने शुरू करेंगे

भोपाल में कहा- हमारी यह कोशिश होगी कि 2028 तक बिजली के रेट न बढ़ें

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधार, बिजली चोरी पर नियंत्रण और किसानों को सस्ती व भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिसिंग व्यवस्था विकसित की जा रही है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर सोलर पंप योजनाओं पर काम तेज किया है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना और कुसुम योजनाओं के तहत प्रदेश में सैकड़ों मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है।

कुसुम-ए योजना में अब तक 603 अनुबंध, जबकि 957 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। कुसुम-सी योजना में भी 24 परियोजनाएं स्थापित हैं, जिनसे 136 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा।

बिजली कंपनियों में 50 हजार नियमित पदों पर भर्ती- बिजली कंपनियों में लंबे समय से भर्ती न होने से उपभोक्ता सेवाओं पर

असर पड़ा था। इस स्थिति को सुधारने के लिए 50 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि ये सभी भर्तियां रेगुलर होंगी, जिससे व्यवस्था में स्थायित्व आएगा।

उपभोक्ताओं को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली- ऊर्जा मंत्री ने यह भी दोहराया कि मध्यप्रदेश में आज भी एक करोड़ 37 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में दी जा रही है। किसानों को दी जाने वाली बिजली पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है एक रुपए की बिजली पर किसान से केवल 7 पैसे लिए जाते हैं।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता को फायदा- स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के हित में है। इससे खपत की निगरानी, सही बिलिंग और सस्ती सौर बिजली का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सस्ती बिजली का लाभ स्मार्ट मीटर के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है।

झुग्गी बस्तियों में बिजली चोरी से वाणिज्यिक हानि- बिजली चोरी के सवाल पर मंत्री ने स्वीकार किया कि शहरी और झुग्गी क्षेत्रों में वाणिज्यिक हानि एक बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए सरकार बिजली थानों की स्थापना, तकनीकी निगरानी और जनजागरूकता अभियान चला रही है।ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 2028 तक बिजली की दरें नहीं बढ़ने दी जाएंगी और आने वाले समय में मध्यप्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंत्रालय में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं संबंधी में बैठक ली।

नवीन के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, उसने मुझे पागल कर दिया

आत्महत्या मामले में इंदौर की लड़की के वीडियो और चैट पर दो गिरफ्तार

इंदौर (एजेंसी)। 19 वर्षीय छात्रा प्रियांशी राव की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नवीन गौर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस केस में सह-आरोपी युवती भूमि उर्फ भूमिका को पुलिस जेल भेज चुकी है। सुसाइड से पहले बनाया गया वीडियो और मोबाइल चैट इस पूरे मामले की अहम कड़ी बने हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

गांव में छुपा था आरोपी

पुलिस के अनुसार नर्मदापुरम निवासी नवीन पिता नारायण गौर सोमवार सुबह अग्रिम जमानत लेने इंदौर पहुंचा था। कोर्ट जाने से पहले ही पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिल गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से नवीन पहले होशंगाबाद रोड के निमनपुर गांव में छिपा हुआ था।

दोनों कैफे का करते थे संचालन

जांच में सामने आया है कि नवीन और प्रियांशी मेघदूत नगर में एक कैफे का संचालन करते थे। दोनों के बीच करीब दो वर्षों से घनिष्ठ संबंध थे और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी दौरान नवीन की नजदीकियां भूमि नाम की युवती से बढ़ी, जिसके बाद प्रियांशी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी।

कमरे में दे दी जान

24 नवंबर को सेज यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रियांशी ने मेघदूत नगर स्थित अपने कमरे में लोहे की चेन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था लेकिन उसके मोबाइल फोन से एक वीडियो और कई चैट मिले। इस वीडियो में प्रियांशी रोते हुए खुद को ठगा हुआ बता रही है और नवीन व भूमि को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहरा रही है। वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही है कि इन्होंने मुझे पागल कर दिया है मैं नवीन के बिना नहीं रह पाऊंगी सॉरी।

भूमि के फोन से लगातार कॉल और मैसेज

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भूमि के मोबाइल से प्रियांशी को लगातार कॉल और मैसेज किए जा रहे थे। इन मैसेज में उसे नवीन से दूर रहने और उसका पीछा छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा नवीन ने कैफे के व्यवसाय में प्रियांशी से पैसे भी लगवाए थे, जिससे वह आर्थिक रूप से भी उलझ गई थी।

अलग रहने लगी थी प्रियांशी

पुलिस का कहना है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर प्रियांशी ने नवीन का कमरा छोड़ दिया था और मेघदूत नगर में अलग रहने लगी थी। आत्महत्या से करीब एक सप्ताह पहले उसने रिश्तेदारों की मदद से नया कमरा लिया था। इसी दौरान नवीन नर्मदापुरम चला गया और भूमि व प्रियांशी के बीच विवाद और बढ़ गया।

एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि मर्ग जांच के दौरान मिले साक्ष्यों, वीडियो और चैट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले से जुड़े अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। मूल रूप से देवास की रहने वाली प्रियांशी दो बहनों में सबसे छोटी थी। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी।

महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मंत्री सुश्री भूरिया

समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिये बालिकाओं के साथ बालकों को भी जागरूक करें

भोपाल (नप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में महिलाओं के उत्थान और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिये 21 विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर आगामी कार्य-योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि बाल विवाह रोकने के सार्थक प्रयास में विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को भी इसकी समझाइश दी जाये उन्हें समाज की कुरीतियों को दूर करने और उनके रोकने के लिये जागरूक किया जाये।

विमुक्त घुमंतू जातियों के उत्थान के लिये करें विशेष प्रयास- उद्योग एवं आदिम जाति विभाग के

संयुक्त प्रयास से वर्किंग वीमेन हॉस्टल की हर जिले में स्थापना की जाये ताकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और बेहतर किया जा सके। मंत्री सुश्री भूरिया ने बैठक में कहा कि महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए तथा जमीनी स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाए।

बैठक में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी बालिका योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मंत्री ने योजनाओं में आ रही चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

सुश्री भूरिया ने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से नवाचार आधारित प्रयासों को बढ़ावा देने और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस के लिए एमपी ट्रांसको को मिला सम्मान

मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय 'पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवॉर्ड'

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश ने विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) को वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस दर्ज करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय 'पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर एमपी ट्रांसको के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की मजबूत ट्रांसमिशन व्यवस्था, तकनीकी दक्षता और सतत सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम ट्रांसमिशन लॉस के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित

मंच से एमपी ट्रांसको की ओर से कार्यपालन अभियंता श्री लोकेश द्विवेदी ने यह सम्मान प्राप्त किया।

मूल्यांकन का आधार- पुरस्कार के लिए यूटिलिटीज़ का चयन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के डेटा तथा विभिन्न राज्य विद्युत कंपनियों की आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया। अवॉर्ड की श्रेणियों में सबसे अधिक लाइन लेंथ मे वृद्धि, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में वृद्धि, बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस जैसे महत्वपूर्ण मानक शामिल रहे।

ट्रांसटेक इंडिया-2025 में हुआ सम्मान- यह सम्मान नई दिल्ली स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका में आयोजित 'ट्रांसटेक इंडिया-2025' कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदान किया गया। यह कॉन्फ्रेंस विद्युत मंत्रालय से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है, जहां नीति निर्माता, रेगुलेटरी संस्थाएं, डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स आपसी समन्वय के साथ भाग लेते हैं। इस आयोजन में देशभर से 2500 से अधिक ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

मंत्री विश्वास सारंग का जिला पांढुर्णा प्रवास

बोरगांव स्थित सेवा सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण

पांढुर्णा (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को जिला पांढुर्णा प्रवास के दौरान बोरगांव स्थित सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समिति के प्रशासकीय कार्यों का विस्तार से अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में लेखाकार द्वारा किए जा रहे संतोषजनक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं समिति के प्रबंधक को (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के माध्यम से नए व्यवसायिक अवसर सृजित करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बोरगांव क्षेत्र में व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता विभाग के नवाचार सीपीपीपी के तहत औद्योगिक कंपनियों के साथ साझेदारी के अवसर तलाशे जाएं, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकें। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी सहकारिता को सशक्त करने और पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सहकारिता विभाग के नवाचार सीपीपीपी के माध्यम से औद्योगिक कंपनियों के साथ साझेदारी के अवसर खोजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी एक ऐसा आयाम है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री श्री सारंग के इस दौरे से सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संदेश गया है। निरीक्षण उपरांत मंत्री श्री सारंग ने सुरुचि मसाला के प्रबंधक के साथ बैठक कर किसानों की आय बढ़ाने एवं पैक्स को नए व्यवसायिक अवसरों से जोड़ने को लेकर विस्तृत चर्चा की।

किसान स्वराज सम्मेलन 11-13 जनवरी को गुजरात में

भोपाल। देश में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों के अधिकारों की रक्षा तथा खेती को पर्यावरण-अनुकूल और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उत्तर एवं पश्चिम भारत का किसान स्वराज सम्मेलन आगामी 11 से 13 जनवरी 2026 तक पालनपुर (बनासकांठा) के पास रतनपुर, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है।इस सम्मेलन का आयोजन एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा) द्वारा किया जा रहा है। आशा पिछले 15 वर्षों से देशभर में किसानों, वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों को जोड़ते हुए प्राकृतिक खेती, बीज स्वराज और टिकाऊ कृषि नीतियों पर कार्य कर रहा है। इससे पहले भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, मैसूर और चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलनों में हजारों लोग भाग ले चुके हैं।सम्मेलन में मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर व पश्चिम भारत के कई राज्यों से किसान, कृषि विशेषज्ञ, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और नीति विश्लेषक भाग लेंगे। विशेष रूप से किसानों के बीज अधिकार, देशी बीजों का संरक्षण, सीड बिल, HT (शाकनाशी-प्रतिरोधी) फसलें और उनके दुष्प्रभाव, रसायन-मुक्त खरपतवार प्रबंधन, खेती में मजदूरों की उपलब्धता, जीन-संपादित फसलें, प्राकृतिक खेती का प्रमाणन एवं बाज़ार, कार्बन क्रेडिट और मुक्त व्यापार समझौतों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा होगी।

मध्यप्रदेश के प्रख्यात प्राकृतिक किसान जनक पाल्टा, बाबूलाल दहिया, शोधकर्ता सौमिक बनर्जी तथा अन्य विशेषज्ञ सम्मेलन में अपने अनुभव साझा करेंगे। राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और टिकाऊ खेती के समाधान खोजने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

सम्मेलन के दौरान देशी बीज प्रदर्शनी, किसानोपयोगी औज़ारों का प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती की पद्धतियों का लाइव प्रदर्शन, फिल्म शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेषज्ञ किसानों के साथ प्रत्यक्ष संवाद जैसे आयोजन भी होंगे।

इस आयोजन में प्रसिद्ध कृषि नीति विश्लेषक देविंदर शर्मा, पद्मश्री से सम्मानित प्राकृतिक किसान सुभाष शर्मा, बीज संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. देबल देव, सामाजिक कार्यकर्ता कविता कुरुगंती सहित देशभर के अनेक जाने-माने वक्ता भाग लेंगे।आयोजन में लोकनिकेतन, रतनपुर और जतन संस्था का विशेष सहयोग है।

सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक किसान, कृषि कार्यकर्ता और संस्थाएँ 3 जनवरी 2026 तक व्हाट्सएप फोनः 9962043710 (दोपहर 2 बजे से शाम 8:30 बजे तक) पर संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन के लिए kisanswarajsammelan2026@gmail.com पर मेल करें।

संपादकीय

महायुति की बंपर जीत !

महाराष्ट्र में हाल में हुए 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की बंपर जीत से साफ हो गया कि अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे, राज्य में स्थानीय चुनाव भी महायुति द्वारा एक साथ लड़ने की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पूरी तरह कारगर रही। महायुति ने कुल 221 स्थानों पर जीत हासिल की, जिसमें भाजपा 124, शिवसेना (शिंदे) 61 तथा राष्ट्रवादी (अजित) को 36 स्थानों पर जीत हासिल हुई। विपक्षी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का ही प्रदर्शन कुछ ठीक रहा उसे 27 स्थानों पर विजय मिली, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मात्र 8 जगह जीत मिली। 20 स्थानों पर अन्य विजयी रहे। हालांकि इस चुनाव में महायुति के बीच आपस में कुछ स्थानों पर शक्ति परीक्षण हुआ। इसमें अंबरनाथ और बदलापुर में शिंदे सेना के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई। दूसरी तरफ, राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा को आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में एक भी सीट न मिलना हैरान करने वाला था। इसी तरह लोहा नगर परिषद में बीजेपी की फैमिली पैक रणनीति फेल हो गई। यहां अध्यक्ष पद के लिए उसके उम्मीदवार गजानन सूर्यवंशी और उनके पांच रिश्तेदार हार गए। गढ़चिरौली में एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी को मात्र एक वोट से हार मिली। जबकि तीन स्थानीय निकायों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीते। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायत के लिए दो चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण में 2 दिसंबर को 263 निकायों में मतदान हुआ था। बाकी 23 नगर परिषदों और कुछ खाली पदों पर 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इनकी मतगणना 21 दिसंबर को हुई। महायुति की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद किया और इसे विकास पर जनता के भरोसे से जोड़ा। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिणामों को सुशासन और विकास की राजनीति की जीत बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे ऐतिहासिक सफलता कहा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण को बधाई दी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने परिणामों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2017 में 94 नगरपालिकाओं की तुलना में इस बार हमने 129 नगरपालिकाओं (45 प्रतिशत) में जीत हासिल की है। महायुति के तौर पर हमने 215 नगरपालिकाएं (74.65 प्रतिशत) जीती हैं। इसी तरह 2017 में भाजपा के 1602 पार्षद थे, जो अब बढ़कर 3325 हो गए हैं। पार्षद की कुल संख्या 6952 है, इनमें से महायुति के 4331 पार्षद जीते हैं। दूसरी तरफ इस हार से बौखलाए विपक्ष ने हार का ठीकरा धनबल पर फोड़ा है। उद्धव सेना के संजय राउत ने कहा कि जीत का आंकड़ा विधानसभा चुनाव वाला ही है। यानी वही मशीन, वही सेटिंग और वही पैसा। इस इलेक्शन में पैसों की बारिश हुई। अलबत्ता इन चुनावों में यह फिर साबित हुआ कि महायुति के घटक दलों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं। हालांकि उद्धव सेना का ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं है। उनकी असल दिलचस्पी महानगर पालिकाओं के और खासकर मुबंई नगर महापालिका के चुनाव में है। जहां उनकी लंबे समय से सत्ता रही है और जो शिवसेना की आर्थिक मजूबती का आधार भी है। दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति मुंबई से उद्धव सेना को जड़ से उखाड़ने की है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। यानी महायुति और मविआ का असल मुकाबला इन चुनावों में होगा। अगर उद्धव की शिवसेना यहां भी हार जाती है तो उसके वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।

कर्नाटक में अपनों में ही उलझ गई कांग्रेस

कर्नाटक की राजनीति

वेद विलास उनियाल

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक

कांग्रेस के लिए अब कर्नाटक गहरी उलझन बन गया। पिछले दिनों चाय पार्टियों और इडली डोसा का स्वाद भी दो नेताओं के बीच की खाई को दूर नहीं कर पा रहा। कांग्रेस हाईकमान के लिए नेतृत्व के मसले में किसी समाधान तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अब किसी भी तरह समझौता करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। अब तो डी शिवकुमार किसी डिनर या इडली दोसे की दावत आयोजित होने से भी इंकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंजे राजनेता की तरह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी। कर्नाटक की राजनीति में दोनों नेता किसी तरह एक दूसरे पर आक्रोश वाले बयानों से बच रहे हैं। इसे उस शांत झील की तरह देखा जा रहा है जिसमें एक कंकड पड़ने की देर है। झील में लहरों की उथल-पुथल कहां तक दिखेगी इसकी थाह लेना मुश्किल है।

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सिरे से ढाई साल सत्ता साझा करने के फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है। अब तक वह गेंद हाईकमान के पाले में डाल कर कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वह उन्हें और उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार को मानना होगा। लेकिन, अब पूरे जोर देकर कह रहे हैं कि सत्ता में वह पांच साल तक बने रहेंगे। सीधा संकेत है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सियासत में उलझन बढ़ गई है। उधर, डी शिवकुमार भी अपने फैसले से पलट नहीं रहे हैं। वह किसी भी स्थिति में अब नेतृत्व चाहते हैं । इन स्थितियों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह आखिर किसके पक्ष में खड़ा हो। इस जटिल पहेली से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिद्धरमैय्या और डी शिवकुमार दोनों ही नेता यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी के पक्ष में जाना आसान नहीं है। हालांकि डी शिवकुमार बगावत की राह पर नहीं दिख रहे । लेकिन जिस तेवर के साथ वो नेतृत्व की बात कर रहे हैं उसमें सिद्धरमैय्या के लिए आगे सत्ता चलाना इतना आसान भी दिख रहा है। इन हालातों में राज्य कांग्रेस पर ही नहीं राज्य की व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं असर पड़ रहा है।

अब एक कदम आगे कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि ढाई साल में नेतृत्व बदलने का कोई समझौता ही नहीं था। वह तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक उच्च नेतृत्व कोई और निर्णय नहीं ले लेता है। वह पूरे कार्यकाल सत्ता में रहेंगे । गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा मं नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सवाल उठाया था कि आपको पार्टी के जरिए पांच साल के लिए चुना गया था ढाई साल का क्या हुआ। इस पर सिद्धारमैया का जवाब था कि कभी ढाई साल की बात नहीं हुआ। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस ने जब ढाई साल पहले कर्नाटक में नेतृत्व के सवाल पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सुलह कराई थी, तब शायद यह अनुमान नहीं रहा होगा कि यह मामला आगे इतना पेचीदा बन जाएगा। कांग्रेस के तब कर्नाटक की जीत के बड़े मायने थे। कांग्रेस इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देख रही थी। इसलिए उस माहौल में वह आगे की राजनीति को न सोचकर अपने पुराने फार्मूले में ही समाधान निकाल रही थी। इसलिए ढाई साल बाद नेतृत्व परिवर्तन पर किसी तरह डी शिवकुमार को मना लिया था। वह सिद्धारमैया सरकार में डिप्टी सीएम बने।

कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि एक तरफ डी शिवकुमार उसके पुराने विश्वस्त हैं। डी शिव कुमार ने कांग्रेस की आर्थिकी को भी किसी हद तक संभाला है। कहा यह भी जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी तरफ से खासा सहयोग हुआ था। जबकि, सिद्धारमैया कांग्रेसी संस्कृति के नहीं है। वह जनता दल (एस) में देवगौड़ा से अनबन के बाद कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस में वह इसलिए स्वीकार्य हो गए कि उनकी अंहिदा राजनीति से उनके जनाधार को कांग्रेस ने अपने हित में माना। किसी हद तक कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। जबकि दूसरी तरफ डी शिवकुमार लिंगायत के बाद प्रबल माने जाने वाली वोकलिग्गा समुदाय से आते हैं। जातीय फैलाव और समायोजन में सिद्धारमैया डी शिवकुमार से ज्यादा अहमियत पाते हैं। यही पर कांग्रेस के लिए उलझन है कि वह डी शिवकुमार को नेतृत्व सौंपे या फिर सिद्धारमैया को ही सत्ता में बनाए रखे। एक हल्की सी आहट यह भी होती है कि क्या इन दोनों के आपसी संघर्षों के बीच किसी तीसरे पर दांव चलाया जाए। लेकिन, यह कहने में जितना सहज लगता है उतना ही जटिल भी है। डी शिवकुमार किसी भी परिस्थिति में नेतृत्व चाहते हैं। वह शायद ही इस बात पर सहमत होंगे कि अगर मैं नहीं तो सिद्धारमैया भी नहीं। कोई तीसरा चल सकता है।

कर्नाटक में कांग्रेस ऐसे भंवर में फंस गई है, जहां उसे सूझ नहीं रहा है कि वह किसके साथ खड़ी दिखे। हाईकमान अपने वादे के मुताबिक डीके शिवकुमार को नेतृत्व नहीं सौप पा रहा है। और डीके शिवकुमार इस तेवर में है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कांग्रेस में अगर व्यवहारिकता देंखे तो नेतृत्व डीके शिवकुमार को सौंपा जाना चाहिए। कांग्रेस हाइकमान ने अपने प्रतिनिधियों के सामने दोनों नेताओं के बीच बारी-बारी से नेतृत्व के लिए समझौता कराया था। गौरतलब है कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। तब राज्य में नेतृत्व को लेकर खासा संघर्ष हुआ था। कांग्रेस नेता सिद्दारमैय्या और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। दोनों ही खेमों से इसके लिए खासी जोरआजमाइश हुई। लंबी राजनीतिक खींचतान पर विराम एक पुराने फार्मुले से ही लगा था। 18 मई 2023 को दोनों नेताओं को बारी बारी ढाई साल नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया गया था। शुरु में आनाकानी करने के बाद आखिर सिद्धारमैय्या को सीएम बनाने के लिए डी के शिवकुमार तैयार हो गए। डी के शिवकुमार राज्य में डिप्टी सीएम बने।

डीके शिवकुमार पहले ढाई साल सीएम बनना चाहते थे। लेकिन सिद्धारमैया ने वरिष्ठता के आधार पर पहले सीएम बनने का हक जताया। तब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे वेणुगोपाल रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं की उपस्थिति में इस फार्मूले पर दोनों नेताओं को सहमत कराया गया था। लेकिन जब ढाई साल की अवधि पूरी हो गई तो डी के शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की बात उठाई। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के अंदर यह डर है कि डी शिवकुमार अगर बगावत करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। वहीं सिद्दारमैया को हटाया जाता है कि वह जिस जातीय संतुलन को ढाल बनाए हैं वह कांग्रेस से दरक सकता है। खासकर तब राहुल गांधी पिछड़ी जातियों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के गुट ने नेतृत्व परिवर्तन के लिए अपनी आवाज तेज कर दी है। उनका कहना है कि कर्नाटक में पार्टी की जीत के बाद नेतृत्व को लेकर जो फार्मूला तय हुआ था उसके आधार पर अब सत्ता डी के शिवकुमार को सौंपी जानी चाहिए।

कांग्रेस के लिए हरियाणा महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में पराजय के बाद कर्नाटक के किले को बचाए रखने की चुनौती है। और यह स्थिति ढाई साल बाद के चुनाव के लिए यहीं कही जा रही है। बल्कि कर्नाटक का यह किला अभी दरकने का संकेत दे रहा है। कांग्रेस ने पहले छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्यप्रदेश में सरकार गंवाई है। उसके हाथ से राज्यों का इस तरह फिसलना गलत संदेश दे रहा है। ऐसे में कर्नाटक उसके सामने एक सवाल बन कर आया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है और किस तरह इस मसले का समाधान तलाशता है इसमें ही उसके आंतरिक प्रबंधन और दक्षता का पता चलेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती दक्षिण में अपने प्रभाव को बनाए रखने की है। उत्तर भारत के हिमाचल के अलावा दक्षिण में तेलंगाना में उसकी सरकार है। तमिलनाडु में उसकी हैसियत इस पर निर्भर करती है कि डीएमके उसे किस तरह रखती है।

केरल में वह जरूर कुछ बेहतर स्थिति में नजर आती है। लेकिन कर्नाटक में अखर बिखराव हुआ तो उत्तर या दक्षिण कांग्रेस के लिए संदेश ठीक नहीं जाएगा। जितनी जल्दी हो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाधान निकालना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का असर दोनों नेताओं का कितना हो सकता है कहना मुश्किल है। इसलिए खरगे भी इशारा दिल्ली की ओर करते हैं। अब कांग्रेस ने दोनों खेमो से कहा है कि वह बंगलूरू में रह कर ही इस मामले को निपटाए । दिल्ली आकर बयान देने से संकेत गलत जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है । कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बहुत मायने रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की दिक्कते बढ गई है। कोई न कोई रास्ता कांग्रेस को निकालना ही होगा।

भूमि की बिगड़ती सेहत और किसान

किसान दिवस पर विशेष

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी वन क्षरण, अत्याधिक कृषि गतिविधियों से भूमि की नमी घटने और उसकी उर्वरता कम होने की समस्या से जूझ रहा है। इन कारणों के चलते भारत की 30 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि की सेहत बिगड़ गई है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास से कृषि भूमि नष्ट हो रही है। वहीं उद्योग, बिजली और सिंचाई व पेयजल के लिए बड़े बांधों के अस्तित्व में आ जाने के कारण दलदली भूमि भी बढ़ रही हैं।यह समस्या मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में सर्वाधिक होने के साथ, इन्हीं राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। इससे 72000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। क्षरण और भूमि के मरुस्थलीकरण से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 प्रतिशत और फसल की पैदावार में भी कमी आई है। इधर खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीएम फसलों की पैदावार ने भी खेतों की सेहत बिगाड़ने का काम बड़ी मात्रा में किया है।

नतीजतन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव भी गहरा गए हैं। वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण की समस्या के समाधान के लिए 450 अरब डॉलर का वार्षिक खर्च आएगा। यदि इसमें सुधार जल्दी नहीं किया गया तो विश्व में 3.2 अरब लोगों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। भारत के लिए यह समस्या इसलिए विकराल है, क्योंकि दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में बसती है, जबकि दुनिया की कुल भूमि का भारत के पास महज 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही है। साफ है, उपजाऊ जमीन का बंजर भूमि में बदलना चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी समिति द्वारा अगस्त-2019 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 23 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत भूमि के क्षरण का है। चुनांचे निकट भविष्य में भूमि में व्यापक सुधार नहीं हुए तो यह समस्या एक प्राकृतिक आपदा में बदलती चली जाएगी।

यह विडंबना ही है कि भारत में रोटी और रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन बनी भूमि की गुणवत्ता अथवा उसकी बिगड़ती सेहत को जांचने का अब तक कोई राष्ट्रव्यापी पैमाना नहीं है। जबकि देश की कुल आबादी में से सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि और प्राकृतिक संपदा से रोजी-रोटी जुटाती है। भूमि की उर्वरता और क्षरण को लेकर टुकड़ों में तो आकलन आते रहते हैं, लेकिन इस स्थिति की वास्तविक हालत का खुलासा करने वाला कोई एक मानचित्र देश की जनता के सामने पेश नहीं किया गया। हालांकि अशासकीय स्तर पर इस मांग की आपूर्ति अहमदाबाद की संस्था 'स्पेस एप्लिकेशन सेंटर' ने सत्रह अन्य इसी काम से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर की है। जमीन की सेहत से जुड़ा यह शोध बताता है कि आधुनिक व औद्योगिक विकास, जल व वायु प्रदूषण और कृषि भूमि में खाद व कीटनाशकों के बढ़ते चलन ने किस तरह से उपयोगी भूमि को रेगिस्तान में तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 'स्पेस एप्लिकेशन सेंटर' द्वारा किए शोध के मुताबिक राजस्थान का 21.77 प्रतिशत, जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख का 12.79 और गुजरात में 12.72 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। मध्यप्रदेश में चंबल के बीहड़ पिछले 60 साल में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर-प्रदेश व मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की कृषि का अनावृष्टि के कारण तेजी से क्षरण हो रहा है। वहीं भू-जल के बेतहाशा दोहन और अल्पवर्षा के चलते खेतों में दस सेंटीमीटर नीचे एक ऐसी कठोर परत बनती जा रही है, जो कालांतर में फसल की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगी।

रेगिस्तान के विस्तार की तह में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का चक्र तो है ही 1999 के बाद से मानसून की दगाबाजी ने उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल देने का काम किया है। इन्हीं वजहों से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र भूमिक्षरण के प्रभाव में आए जंगलों का विनाश, चरनोई की भूमि को कृषि व आवासीय भूमि में तब्दील करना और एक तरह की फसल पैदा करने के बढ़ते चलन से भूमि की सेहत बिगड़ी है। कुछ ऐसी ही वजहों के चलते बर्फीली वादियों से लेकर घने वनों वाले क्षेत्र भी फैलते रेगिस्तान की गिरफ्त में आ गए हैं।

जिस हरित क्रांति के बूते पंजाब को भारत का अनाज के अटूट भंडार का दर्जा हासिल हुआ था, वही पंजाब आज रासायनिक खादों का बेतहाशा उपयोग करने के कारण बड़ी तादात में अपनी कृषि भूमि बरबाद कर चुका है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का 1.5 प्रतिशत भाग पंजाब के हिस्से में है। जबकि देश में कीटनाशकों की कुल खपत का 18 फीसदी उपयोग पंजाब के किसान करते हैं। इसी तरह पंजाब के मालवा क्षेत्र का कपास क्षेत्र पूरे पंजाब का केवल 15 फीसदी है, जबकि यहां पंजाब के कुल कीटनाशकों की खपत 70 फीसदी है। पंजाब के मालवा का क्षेत्र देश के कुल भू-भाग का मात्र 0.5 भाग है, जबकि यहां देश में कुल खपत होने वाले कीटनाशकों की 10 फीसदी खपत होती है। जिस भांखड़ा नांगल बांध को हम पंजाब की उन्नत खेती का आधार मानते हैं, इस बांध से जल रिसाब के चलते पंजाब की अब तक ढ़ाई लाख हेक्टेयर कृषि भूमि दलदल में बदल चुकी है। यही नहीं कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने यहां कैंसर की बीमारी को बड़ी आबादी में परोस दिया है।

कृषि के आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण ने भी भूमि की सेहत को बिगाड़ने का काम किया है। इस बाबत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किए गए एक शोध के मुताबिक इस अंचल की भूमि में दो तरह के विकार पैदा हुए हैं। एक कृषि भूमि की सतह में दस सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत (हार्ड-लेयर) बन गई है। दूसरे, भू-गर्भ में करीब एक सौ मीटर की गहराई पर पानी से भरी रहने वाली जगह (पोर-स्पेस) रिक्त पड़ी है। क्षेत्रीय पर्यावरण में आए ये परिवर्तन भू-गर्भीय अथवा सतह पर भूकंप जैसी हलचल की वजह भी बन सकते हैं। डिस्कवरी चैनल द्वारा इस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण ने भी दावा किया है कि चंबल व ग्वालियर अंचल में तेजी से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।

इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा परंपरागत खेती को नकारने से हुआ। पहले हलों से खेतों की जुताई होती थी लेकिन अब हैरो, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरणों से हो रही है। ये जमीन को आठ से बारह सेंटीमीटर तक गहरा जोत कर भूमि की ऊपरी परत को उधेड़ कर पलट देते हैं। नतीजतन मिट्टी सूख कर शुष्क होती जा रही है और वहीं इसके नीचे की परत कठोर। यह परत अब इतनी कठोर हो गई है कि खेतों की मिट्टी का आनुपातिक कुदरती जैविक समीकरण ही गड़बड़ा गया है।

इधर चंबल क्षेत्र में भूमि के लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण ने बीहड़ों के विस्तार का ऐसा भयावह सिलसिला जारी रखा हुआ है, जो गांव के गांव लीलता जा रहा है। इस अंचल के भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में हर साल पन्द्रह सौ एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है। इन जिलों की कुल भूमि का 25 फीसदी हिस्सा बीहड़ों का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बीहड़ों का विस्तार है। इन तीनों जिलों के क्षेत्र में जितनी भी छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, वे जैसे बीहड़ों के निर्माण के लिए अभिशप्त हैं। चंबल में 80 हजार, कुआंरी में 75, आसन में 2036, सीप में 1100, बैसाली में 1000, कूनों में 8072, पार्वती में 700, सांक में 2122 और सिंध में 2032 हेक्टेयर बीहड़ हैं। बीते दस सालों में करीब 45 प्रतिशत बीहड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन बीहड़ों का जिस गति से विस्तार हो रहा है, उसके मुताबिक 2050 तक 55 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बीहड़ों में तब्दील हो जाएगी। नतीजतन करीब दो हजार आबाद गांव बीहड़ लील लेंगे। इन बीहड़ों का विस्तार एक बड़ी आबादी के लिए विस्थापन का संकट पैदा करेगा ?

जमीन की सेहत अब प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानव उत्सर्जित कारणों से ज्यादा बिगड़ रही है। पहले भूमि का उपयोग रहवास और कृषि कार्यों के लिए होता था, लेकिन अब औद्योगीकरण, शहरीकरण, बड़े बांध और बढ़ती आबादी के दबाव भी भूमि को संकट में डाल रहे हैं। जमीन का खनन करके जहां उसे छलनी बनाया जा रहा है, वहीं जंगलों का विनाश करके जमीन को बंजर बनाए जाने का सिलसिला जारी है। जमीन की सतह पर ज्यादा फसल उपजाने का दबाव है तो भू-गर्भ से जल, तेल व गैसों के अंधाधुंध दोहन के हालात भी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के जो नलकूप जैसे आधुनिक संसाधन हरित क्रांति के उपाय साबित हुए थे, वही उपाय खेतों में पानी ज्यादा मात्रा में छोड़े जाने के कारण कृषि भूमि को क्षारीय भूमि में बदलने के कारक सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की सेहत अलग-अलग कारणों से प्रभावित हो रही है, जिसकी देशव्यापी पड़ताल अब तक नहीं हुई है। धरती की बिगड़ती इस सेहत को मानचित्र पर लाना जरुरी है।

यदि वोटर हो तो साबित करो

कटाक्ष

श्याम यादव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

लोकतंत्र में अब वोट डालना सबसे सरल और वोटर बने रहना सबसे जटिल काम हो गया है। उंगली पर स्याही लगवाने में एक मिनट लगता है, लेकिन यह साबित करने में कि उंगली आपकी ही है, पूरा जीवन लग सकता है। इन दिनों यही अभ्यास पूरे भरोसे के साथ चल रहा है, जिसे नाम दिया गया है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी शार्ट फार्म में एसआईआर।

अब बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं। वे अकेले नहीं आते, उनके साथ प्रक्रिया आती है। प्रक्रिया का पहला वाक्य हमेशा आश्वस्त करता है घबराने की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में जब यह कहा जाता है, तो नागरिक समझ जाता है कि अब उसे शांत रहकर सब कुछ बताना है। दरवाज़ा खुलते ही नाम पूछा जाता है। नाम बताने के बाद भी नाम पूरा नहीं होता। फिर पता पूछा जाता है। पता वही है, लेकिन अब वह सिर्फ़ रहने की जगह नहीं, एक संदिग्ध सूचना बन चुका है। नागरिक समझने लगता है कि पहचान अब सामाजिक नहीं रही, वह प्रशासनिक हो चुकी है।

मतदाता कहता है कि मैं वोटर हूँ। जवाब आता है, तो साबित कीजिए। लोकतंत्र की भाषा में यह कोई अपमान नहीं है, यह प्रक्रिया है। प्रक्रिया में आदमी को अपने बारे में वही साबित करना होता है, जो अब तक उसे स्वाभाविक लगता था। मकान पहचानता है, गली पहचानती है, पड़ोस पहचानता है। लेकिन, काग़ज़ सोच में पड़ जाता है। काग़ज़ों की अपनी राजनीति है। बहुत पुराने काग़ज़ इतिहास कहलाते हैं, बहुत नए काग़ज़ संदेह। एक काग़ज़ कम हो तो नागरिक अधूरा, ज़्यादा हो तो चालाक समझा जाता है।

बीएलओ सवाल पूछते हैं पहला वोट कब और कहां डाला था? नागरिक सोचता है कि यह चुनावी जानकारी है या स्मृति परीक्षा। लोकतंत्र में अब याददाश्त भी पात्रता बन चुकी है। जो भूल गया, वह संदिग्ध है। जो बहुत कुछ याद रखता है, वह भी। पड़ोसी गवाही देना चाहते हैं। उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह नागरिक अकेला नहीं रहता। पूरा मोहल्ला लोकतंत्र की कतार में खड़ा हो जाता है। लोकतंत्र सामूहिकता सिखाता है कियह उसका व्यावहारिक उदाहरण है।

हर चरण पर बताया जाता है कि यह सब नागरिकों के हित में है। हित का अर्थ यहाँ सुविधा नहीं, संतोष है। नागरिक को संतोष रखना है कि जाँच हो रही है। सवाल प्रक्रिया पर नहीं उठाए जाते। सवाल सिर्फ़ नागरिक से पूछे जाते हैं। प्रक्रिया सवालों से ऊपर रहती है। अंत में वही वाक्य आता है 'यह सिर्फ़ एक प्रक्रिया है।' यह वाक्य लोकतंत्र का सबसे सुरक्षित कवच बन चुका है। इसके भीतर असुविधा भी वैध है, असमंजस भी और लंबा इंतज़ार भी। नागरिक को सहयोग करना है, क्योंकि सहयोग अब कर्तव्य का नया नाम है।

मतदाता मुस्कराता है। यह मुस्कान सहमति की नहीं, आदत की है। उसे बताया जाता है कि अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन वह देख रहा है कि अधिकार जितने अमूर्त होते जा रहे हैं, उन्हें साबित करने की ज़िम्मेदारी उतनी ही ठोस होती जा रही है। देश आश्वस्त है। पुनरीक्षण चल रहा है। सूचियाँ सुधारी जा रही हैं। लोकतंत्र सक्रिय बताया जा रहा है। बस नागरिक को यह याद रखना है कि अब लोकतंत्र में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि आपने किसे वोट दिया, बल्कि यह है कि आप वोटर साबित हो पाए या नहीं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बब्बन चाचा और समाज सेवा का अधूरा सपना

व्यंग्य

डॉ. मुकेश असीमित

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जैसे ही बब्बन चाचा सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए, शहर में कुकरमुत्तों की तरह उग आई संस्थाओं ने उन्हें सर आंखों और माथे पर बिठा लिया। दरअसल, सेवानिवृत्त होने से पहले ही वह समाज सेवा का मन बना चुके थे। संस्थाओं ने उनकी इस मनोवृत्ति को सूंघ लिया – आखिर संस्थाएं बनी ही इसलिए हैं कि कोई तो ऐसा मिले जिसे सेवा का कीड़ा काटे, और फिर संस्थाएं उससे सेवा करवा सकें!

उनके सेवानिवृत्ति समारोह में सभी लोग अपने-अपने सेवा 'मेनू कार्ड' लेकर उनके पास पहुँच गए। विकल्प सुझाए गए – 'बताइए, आपको किस प्रकार की सेवा करनी है? हमारी संस्था हर प्रकार की समाज सेवा में अग्रणी है।' सदस्यता पैकेज से लेकर रक्तदान, केले, कंबल, कपड़े – जो भी हो, सब कुछ दान के साथ ही उपलब्ध। सभी के पास लाभार्थियों की 'प्रामाणिक सूची', अखबारों से सांठगांठ, नित्य छपने की गारंटी, सम्मान, पदक और सरकार से भी दो-चार अलंकरण दिला देने की गारंटी!

कुल मिलाकर, संस्थाओं के पास समाजसेवा को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने 'साम', 'दाम', 'दंड', 'भेद' के तरीके मौजूद हैं, ताकि सेवा येन केन प्रकारेन हो ही जाए बस। अब जीवन की बची हुई फूँक से समाज की सेवा में जान फूँक देने का उनका जज़्बा देखते ही बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज सेवा चाचा के लिए कोई मिशन नहीं, एक 'मिसफ़ायर' जैसा कुछ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, हमने पूरी तहकीकात करके जो शोध रिपोर्ट हासिल की है, वो अब आपको बताते हैं!

इसके लिए हमने अपने कई ख़ुफ़िया स्रोत–जो उनके मित्र कहलाते हैं– बब्बन चाची, उनके बच्चे, आस-पड़ोस, कुछ दीवारें जिनके कान होते हैं, उनके अपने कान लगाकर सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया है और अब थोड़ा बहुत तोड़-मरोड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो यह सिलसिला आज से दो साल पहले शुरू हुआ। इस बीच में चार-पाँच संस्थाएँ चाचा ने जॉइन कीं। सिफ़ारिश कहीं नहीं लगानी पड़ी। संस्थाएँ एक जोड़ी जातीं, दूसरी छूटती जातीं। किसी भी संस्था में एक या दो महीने से ज़्यादा नहीं टिके। या तो वे दूसरी संस्था को मौका देना चाहते थे या उसी संस्था में किसी और को। कारण कुछ भी हो सकता है। चाचा ने पहली संस्था जॉइन की–उसके पहले ही प्रोग्राम में ऐसा अनुभव हुआ कि 'सर मुंडाते ही ओले पड़ गए।' संस्था का शपथ ग्रहण समारोह था।

कार्यक्रम बढ़िया था, सब ठीक-ठाक संपन्न हुआ। शपथ लेते वक्त कैमरे वाले को विशेष रूप से अपनी दूर की जान पहचान का हवाला देते हुए और पोते के मुंडन संस्कार में बुलाने का वादा करके बढ़िया-सी फोटो भी खिंचवाई।

लेकिन संस्था के अध्यक्ष ने उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया–अपना खुद का फ़ोटो संस्था की न्यूज़ में लगवा दिया। दूसरे एडिशन में बब्बन का फ़ोटो नदारद पाकर और बब्बन की वर्तनी को 'बाबन' कर देने पर नाराज़ होकर फ़ोन कर दिया–

'आप मेरी सदस्यता वापस करें जी!'

दूसरी संस्था ने उनका नाम तो दर्ज कर लिया, पर संस्था के लैटर हेड में नहीं छपवाया। वह अपना नाम ढूंढते रह गए। काउंसिल के मेम्बर थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि 'चिंता न करें नए मेम्बर, अगली साल ऐड होंगे।' बताइए ज़रा! संस्था की फीस तो पहले साल भी लगी थी, फिर कैसे होगी समाज सेवा?

अब कोई ज्ञापन दें, किसी अधिकारी से मिलें, पोस्टर-बैनर बनें–सबके लिए नाम तो होना चैये की नहीं।

इसी वादे के मुताबिक बब्बन चाचा जुट पड़े पूरी तरह संस्था की सेवा करने के लिए –खूब खिलाया। पिलाया, संस्था की कोर कमेटी को अपनी हैं हैं ब्रांड चापलूसी मुद्रा भाव के नाच से रिझाया, डोनेशन भी दिया। लेकिन संस्था में छोड़े गए अपने कुछ गुप्त सूत्रों से पता लगा कि किसी और को अध्यक्ष पद दिया जा रहा है।

बब्बन खफ़ा होकर वहाँ से चले आए।

एक संस्था ने तो हद ही कर दी–उनकी एनिवर्सरी पर 10 रुपये की माला पहनाई गई! बताइए, जबकि उससे पहले एक दूसरे सदस्य की एनिवर्सरी पर 20 रुपये की माला थी। इस अपमान से उनका कोमल हिर्दय छुई मुई की तरह कुम्हला गया ,उन्होंने तुरंत अपने सेवा पंखों को फैलाने से पहले ही समेट लिया। वो सेवा कार्य बीच में ही छोड़कर चले आए।

एक संस्था में उन्हें मंच पर नहीं बिठाया गया। उन्होंने एक बार क्या कह दिया कि वो ज़मीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उन्हें पद, मंच, माला, माइक की कोई ज़रूरत नहीं है–उन्हें इतने गंभीरता से ले लिया गया कि वाकई में मंच से हटा दिया गया!

एक संस्था ने तो हद की सारी हदें पार कर दीं। संस्था का व्हाट्सऐप ग्रुप था–सेवा कार्यों को विस्तार देने के लिए। शहर में सेवा कार्यों को हथियाने की होड़ में एक व्हाट्सऐप ग्रुप बना जहाँ कहीं भी कोई सेवा कार्य दिखे,बस लपकने के लिए ,उसकी गुप्त सूचना देने के लिए ताकि कोई और संस्था उसे हथिया न ले।

इस ग्रुप में बब्बन चाचा के बड़बोलेपन और सेवा की उठती चूल को देखकर उन्हें जोड़ तो लिया गया, लेकिन एडमिन नहीं बनाया गया!

यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है–बिना एडमिन अधिकार के सेवा के बारे में चर्चा करना अब उन्हें सेवा और खुद की दोनों की तौहीन लगने लगी।

वो अपने सेवा-आइडिया को अपने ही हलक में दबाए, वहाँ से सटक लिए।

अब क्या करें बब्बन चाचा? विकल्प है भी क्या? बिना सेवा किए उनका मुँह सिवा लटकने के और कर ही क्या सकता था भला!

कोई है संस्था, जो उन्हें लटका सके, सेवा की साइकिल के करियर पर उन्हें लाद सके?

सेवा के गठरियें उनके माथे पर तनिक भारी तो हैं मित्र! संस्था खुद ही सेवा में इतनी घिचपिच मचाए है...

भीतर भरा है सेवा का कोठा–बाहर ड्रॉइंग रूम में सेवा की डीलें चल रही हैं।

पद, माला, माइक से नाम, प्रतिष्ठा, अवसरों को भुनाने की डील।

सब कुछ हो रहा है सेवा के नाम पर ही–लेकिन वह कैद है संस्था की इस कालकोठरी में... इस घुटन में!

कोई है जो सुनेगा बब्बन चाचा की भी?

रोज़ ऐसे ही बब्बन चाचा हर बार समाज सेवा से थोड़ा-थोड़ा वंचित होते चले जा रहे हैं।

प्रथम पुण्यतिथि

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता

समाज को दिशा दिखाता श्याम बेनेगल का सिनेमा

सत्तर के दशक के सिनेमा में बाजार की हिंसा और एकल नायक का प्रभुत्व था। जो अकेला ही इस व्यवस्था से निबटने में सक्षम है और पूरा समाज इस नायक की प्रतीक्षा करते हुए व्यवस्थागत हिंसा को बर्दाश्त करता रहता है लेकिन इसके बरक्स व्यवस्था परिवर्तन और सामूहिक प्रयासों को भी सिनेमा में शामिल किया गया। श्याम बेनेगल की पहली फिल्म 'अंकुर' 1973 में आयी थी। जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के यथाथ को दिखाती है। जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी सामंती प्रणाली और उससे उपजा उत्पीड़न और शोषण आज भी समाज में व्याप्त है। इस सामाजिक उत्पीड़न से टकराए बिना नए समाज का निर्माण संभव नहीं है। ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि में निर्मित इस फिल्म में जमींदार का एक गरीब मुलाजिम जो मूक बधिर है और जिसे शराब की लत है वह ताड़ी की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। दंड देने के लिए जमींदार उसका सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता है।

भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में 1970 का दशक कई सारे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के लिए जाना जाता है। राजनीति के क्षितिज पर 'गरीबी हटाओ' की मुहिम जोरों पर थी। वहीं सामाजिक तौर पर 70 के दशक में महिलाओं ने एकजुट हो लामबंद होना शुरू किया था। इसी वर्ष से महिला आंदोलनों की शुरुआत होती है। समाज और राजनीति के इन बदलावों को भारतीय सिनेमा में भी महसूस किया जा सकता है। सत्तर के दशक के सिनेमा में बाजार की हिंसा और एकल नायक का प्रभुत्व था। जो अकेला ही इस व्यवस्था से निबटने में सक्षम है और पूरा समाज इस नायक की प्रतीक्षा करते हुए व्यवस्थागत हिंसा को बर्दाश्त करता रहता है लेकिन इसके बरक्स व्यवस्था परिवर्तन और सामूहिक प्रयासों को भी सिनेमा में शामिल किया गया। श्याम बेनेगल की पहली फिल्म 'अंकुर' 1973 में आयी थी। जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के यथाथ को दिखाती है। जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी सामंती प्रणाली और उससे उपजा उत्पीड़न और शोषण आज भी समाज में व्याप्त है। इस सामाजिक उत्पीड़न से टकराए बिना नए समाज का निर्माण संभव नहीं है। ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि में निर्मित इस फिल्म में जमींदार का एक गरीब मुलाजिम जो मूक बधिर है और जिसे शराब की लत है वह ताड़ी की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। दंड देने के लिए जमींदार उसका सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता है। ताड़ के पेड़ से ताड़ी की छोटी सी चोरी की सजा के तौर पर सर के बालों को मुंडवा देना और गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाना गांव के सामंती चरित्र को उजागर करता है और गांव के अन्य व्यक्तियों में अपनी दहशत को बनाए रखने का काम भी करता है। इस घटना से आहत हो किस्तैय्या (साधु मेहर) गांव छोड़कर चला जाता है। आज भी गांवों में इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया को देखा जा सकता है। जिसमें रसूखदार तबका जाति,धर्म और लिंग के आधार पर दंड का निर्धारण करता है और बाकी लोग इस तरह के निर्णय का प्रतिकार करने की बजाए वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर या सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और जो इन्हें देखते हैं वे इमोजी के माध्यम से प्रतिकार कर लेते हैं। फिल्म में जमींदार किस्तैय्या (साधु मेहर) के गांव से चले जाने के बाद उसकी की पत्नी (लक्ष्मी) को अपने ही घर में रख लेता है जो पहले घर में सिर्फ साफ सफाई का कार्य करती थी अब जमींदार उसका यौन शोषण इस आश्वासन के साथ करता है कि वह उसका और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

जमींदार के कारनामों की भनक उसके पिता को लगती है और वे उसकी पत्नी को वहां भेज देते हैं जिसे लक्ष्मी का घर मे रहना पसंद नहीं है और वह उसे काम से निकाल देती है। लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है जब जमींदार को पता चलता है तो वह उसे गर्भपात कराने के लिए कहता है लेकिन लक्ष्मी गर्भपात कराने से इनकार कर देती है और खेत में काम करने लगती है। एक दिन अचानक उसका पति (साधु मेहर) वापस आ जाता है जो लक्ष्मी के गर्भवती होने पर खुश है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह फिर से जमींदार के पास काम मांगने जाता है लक्ष्मी मना करती है लेकिन फिर भी वह चला जाता है। किस्तैय्या को अपनी ओर आते देख जमींदार डर जाता है और दूसरे मुलाजिमों से उसे पकड़वा कर कोड़े से पीटता है। किस्तैय्या जमींदार के हर अत्याचार को सहने के लिए विवश हैं वह किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता। विरोध सिर्फ लक्ष्मी करती है अपने पति की लाचारी और पीड़ा का अपने साथ हुए यौन-शोषण का वो जमींदार को बहुत कोसती है। पूरे गांव से कहीं कोई आवाज नहीं आती है कोई विरोध नहीं करता और आखिरकार जमींदार का विरोध करे भी तो कौन? लेकिन लक्ष्मी के विलाप को जमींदार दरवाजा बंद किए हुए सुन रहा है। इस फिल्म में ग्रामीण आंचलिक परिवेश को बड़ी ही सजीवता के साथ फिल्माया गया है। जो फिल्मों से निर्मित गांव की और गांव के लोगों की छवि को तोड़ती है और उसे नग्न सत्य के साथ पेश करती है। गांव में अपहरण,बलात्कार,सामंती रंगदारी और जबरन वसूली भी शामिल हैं। फिल्म में गांव का बाजार

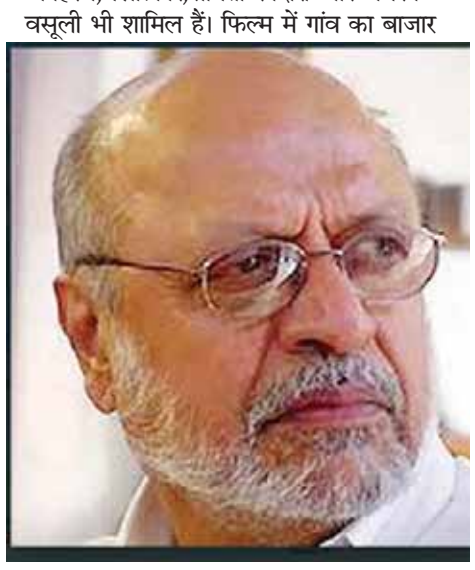

भी मौजूद है जिसमें सब्जी,अनाज और रोजमर्रा की वस्तुएं भी लेकिन इसी के साथ इस बाजार पर जमींदार के नियंत्रण और उसके परिवार के आतंक को भी दर्शाया गया है। पूरा मामला पूंजी का है और इसी से समाज व्यवस्था संचालित हो रही है।

श्याम बेनेगल पूरी फिल्म में यह बात कहीं नहीं कहते है लेकिन फिल्म दर्शक तक यह संदेश प्रेषित कर देती है। इस वास्तविकता का चित्रण करना भी श्याम बेनेगल के लिए उस समय जोखिम भरा रहा होगा। ग्रामीण विषमता पर फिल्म बनाना और उसे प्रमाणिकता के साथ पर्दे पर अंकित कर देना निश्चित रूप से दृढ़ता का परिचायक है। फिल्म के पार्श्व संगीत में हिंदुस्तानी वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल भी एक मैसेज देता है। जिस समय फिल्मों में पार्श्व संगीत में पाश्चात्य वाद्ययंत्रों की भरमार थी या कहें ऑर्केस्ट्रा का दौर था उसमें गांव के वाद्य यंत्रों जैसे शहनाई,झालर और गले में लटके तबले पर लकड़ी की कमची की थाप इत्यादि का इस्तेमाल गांव के लोक और संस्कृति को बचाने और इससे जोड़ने का प्रयास भी है। फिल्म के अंत में एक बच्चा जमींदार के घर पर पत्थर फेंकता है और उसके घर का शीशा चटक जाता है। यह दृश्य गांव की सामंती व्यवस्था में एक बदलाव का एक सूचक है। अंकुर फिल्म के बाद श्याम बेनेगल की दूसरी फिल्म निशांत है इसकी पृष्ठभूमि भी गांव है और उसमें स्त्री उत्पीड़न को दिखाया गया है। इस फ़िल्म में जमींदार के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को दिखाया गया है। पूरा गांव संगठित हो सामूहिक रूप में अपने उत्पीड़क जमींदार पर हमला करता है। इन दोनों फिल्मों का अंत नाटकीय न होकर वास्तविक लगता है जो प्रचलित सिनेमा की अवधारणा को तोड़ता है। श्याम बेनेगल फिल्मों को देखने की दृष्टि बदल देते हैं और अपनी फिल्मों के लिए दर्शक बनाने का प्रयास भी करते हैं। भारतीय सिनेमा पर यूरोपीय कला सिनेमा,अमेरिका के प्रति-सिनेमा और फ्रांस के अवांगार्द सिनेमा के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे यह खुद स्वीकार करते हैं कि उनकी फिल्म 'पाथेर पांचाली' पर इतालवी फिल्मकार डि सिका की कृति 'बाइसकिल थीफ' और फ्रांसीसी फिल्मकार ज्यां रेनुआ की 'दि रिवर' का प्रभाव है। डि सिका के नवयथार्थवाद ने बिमल राय को भी प्रभावित किया था और नवयथार्थवाद से प्रभावित हो बिमल राय ने 1953 में ही 'दो बीघा जमीन' फिल्म का निर्माण कर विश्व में भारतीय फिल्म की उपस्थिति दर्ज कर दी थी। साठ के दशक में मृणाल सेन, मणि कौल और कुमार शाहीन की फिल्मों में इसी परंपरा का अगला चरण दिखाई पड़ता है। कलात्मक सिनेमा की यह धारा सत्तर के दशक में फिल्मकारों की नयी पीढ़ी के रूप में विकसित हुई जिसके शीर्ष पर श्याम बेनेगल थे। जिन्होंने इस दौर में अंकुर, निशांत,मंथन,भूमिका और मंडी जैसी फिल्मों का निर्माण कर अपनी उपस्थित दर्ज की। यह समांतर सिनेमा का दूसरा दौर था। गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था कि 'कला का स्वरूप अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार बदलता जाता है। मेरा विश्वास है कि नई कला जिसका विकास चलचित्रों के माध्यम से संभव है,वह अभी तक रूपायित नहीं हो पाई है। प्रत्येक कला अपनी अभिव्यक्ति की स्वाधीनता शैली अपने रचना जगत में तलाश लेती है। सिनेमा के लिए सृजनशीलता ही काफी नहीं, उसके लिए पूंजी भी आवश्यक है और सिनेमा में बिंबों के प्रभाव के माध्यम से अभिव्यक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है'। श्याम बेनेगल ने कला सिनेमा की विधा में परिवर्तन भी किए क्योंकि पूंजी का मुकाबला बलपूर्वक नहीं किया जा सकता है। इन पूंजीवादी साधनों का इस्तेमाल किस प्रकार से अपने पक्ष में किया जाए यह महवपूर्ण है और इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल श्याम बेनेगल अपनी फिल्म 'जुबैदा', 'वेलडन अब्बा' और 'वेलकम टू सज्जनपुर' में करते हैं हालांकि इन्हें लोकप्रिय/कमर्शियल फिल्मों में रखा गया जो बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब भी रही लेकिन इन फिल्मों में कला फिल्मों की प्रतिबद्धता को भी देखा जा सकता है जो यथार्थपरक सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। आज श्याम बेनेगल की प्रथम पुण्यतिथि है उन्हें शत शत नमन भले ही वे भौतिक रुप से हमारे साथ न हो लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और कलात्मक रूप से प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

दृष्टिकोण

मनीषा मंजरी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

निजता, नैतिकता और डिजिटल समाज

मनुष्य के मौलिक अधिकारों में निजता के अधिकार को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये कोई आधुनिक अवधारणा नहीं बल्कि हमारे संविधान में उल्लेखित अधिकार है। ये अधिकार एक ऐसी सीमा रेखा खींचता है, जिसके भीतर व्यक्ति बिना भय, बिना दबाव, और बिना सार्वजनिक के स्वयं का हो सकता है। परन्तु सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने इस सीमा पर घातक प्रहार किये हैं। आजकल हर एक दृश्य, हर बातचीत, हर भावनात्मक क्षण को रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना सामान्य व्यवहार में शामिल हो चुका है।

डिजिटल दुनिया ने जीवन की सरलता को नए शिखर पर ला कर खड़ा कर दिया है। हर काम से लेकर हर अभिव्यक्ति हमारी उंगिलयों के अधीन हो चुकी हैं। पर अभिव्यक्ति के सरलीकरण के साथ, एक गंभीर चुनौती भी हमारे सामने आयी है, जो है निजता का क्षरण। आधुनिक दौर में समाज ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां किसी व्यक्ति के निजी क्षण, भावनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत सम्बन्ध सब कुछ सार्वजनिक चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। कुछ हीं पलों में कोई भी निजी अनुभव 'वायरल सामग्री' में बदल जाता है। यह स्थिति सिर्फ आधुनिक तकनीकी का परिणाम नहीं अपितु हमारी सामूहिक सोच का भी प्रतिबिम्ब है।

निजता एक मौलिक अधिकार

मनुष्य के मौलिक अधिकारों में निजता के अधिकार को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये कोई आधुनिक अवधारणा नहीं बल्कि हमारे संविधान में उल्लिखित अधिकार है। ये अधिकार एक ऐसी सीमा रेखा खींचता है, जिसके भीतर व्यक्ति बिना भय, बिना दबाव, और बिना सार्वजनिक के स्वयं का हो सकता है। परन्तु सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने इस सीमा पर घातक प्रहार किये हैं। आजकल हर एक दृश्य, हर बातचीत, हर भावनात्मक क्षण को रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना सामान्य व्यवहार में शामिल हो चुका है।

सहमति की अनदेखी

और ये समस्या सिर्फ रिकॉर्ड करने तक सिमित नहीं है बल्कि सहमति की अनदेखी भी है। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक और मानवीय मूल्यों के भी विरुद्ध है। पर विडंबना ये है कि निजता भंग करने की इस प्रवृत्ति को बहुत हीं सामान्य और तुच्छ मानकर अनदेखा किया जाता है।

नैतिकता पर चयनात्मक चुप्पी

हमारे समाज में 'संस्कार', 'मर्यादा' और 'नैतिकता' की बातें बहुत हीं बढ़ा चढ़ा कर की जाती हैं, विशेषकर तब, जब बात रिश्तों और व्यक्तिगत आचरण की होती है। किंतु जब किसी की निजता सार्वजनिक की जाती है, तब यही नैतिकता मौन क्यों हो जाती है? क्या किसी की भावनात्मक स्थिति को सार्वजनिक मंच पर परोस देना अनैतिक नहीं है?

भावनाएँ और सामाजिक विरोधाभास

यूँ तो समाज में भावनात्मक परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है, परन्तु भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। किसी रिश्ते को सम्मानपूर्वक समाप्त करना या अतीत से शांति से विदा लेना स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। इसके बावजूद ऐसे निर्णयों को संदेह और शर्म की दृष्टि से देखा जाता है।

स्त्रियाँ और दोहरा मापदंड

यह असंवेदनशीलता तब और गहरी हो जाती है जब विषय स्त्रियों से जुड़ा हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे त्याग करें, चुप रहें और अपने अतीत को पीछे छोड़ दें। जहां पुरुषों का अतीत अनुभव माना जाता है, वहीं स्त्रियों के अतीत को उनके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। डिजिटल मंचों ने इस दोहरे मापदंड को और अधिक सार्वजनिक तथा आक्रामक बना दिया है।

कमेंट बॉक्स में खुला न्यायालय

आजकल फैसले घरों या समाज की सीमाओं में नहीं होते। वे कमेंट बॉक्स, रील्स और ट्रेंडिंग चर्चाओं में दिए जाते हैं, वह भी बिना संदर्भ और बिना ज़िम्मेदारी के। कुछ सेकंड की दृश्य सामग्री किसी व्यक्ति की पूरी पहचान तय करने लगती है। ना सत्य से किसी को वास्ता होता है और ना हीं निजता पर मौन लिया जाता है।

स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भले हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, पर इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी जुड़ी है। बिना सोचे साझा की गई सामग्री कई बार मानसिक हिंसा का रूप ले लेती है। ऐसी सामग्री को देखना, साझा करना या उस पर टिप्पणी करना, इन सबमें हम अनजाने में हीं उस हिंसा का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं।

सम्मान का वास्तविक अर्थ

सम्मान केवल रिश्तों में हीं ईमानदारी बरतना नहीं होता, बल्कि सम्मान का अर्थ हमें अपनी और सामने वालों की सीमाओं को समझना भी सिखाता है। यह स्वीकार करना कि हर कहानी सार्वजनिक विमर्श का विषय नहीं होती। हर चुप्पी अपराध नहीं होती, हर विदाई और हर आगमन पर सवाल उठाना आवश्यक नहीं होता।

डिजिटल संवेदनशीलता की आवश्यकता

आज आवश्यकता है डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ डिजिटल संवेदनशीलता की। तकनीक का उपयोग मानवता को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए होना चाहिए। शेयर करने से पहले ठहरना, टिप्पणी करने से पहले सोचना, और देखने से पहले समझने की कोशिश करना–यही एक जिम्मेदार डिजिटल समाज की पहचान हो सकती है। यह विषय किसी एक घटना या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह हमारी सामूहिक चेतना पर प्रश्न है, क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे, या इंसान बने रहना भी चुनेंगे?

जन्म दिन विशेष

विजय जोशी

पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक, भेल

संतश्री सिद्ध भाऊजी - एक ही नाम सारे धाम

मानस की शुद्धि हेतु स्वाध्याय की महिमा सर्वविदित है। महात्मा गांधी भी स्वाध्याय के सबसे बड़े सूत्रधार थे: जीयो ऐसे जैसे कल मर जाना हो और सीखो ऐसे जैसे आजीवन रहना हो। स्वाध्याय के प्रति भाऊजी की अभिरुचि स्वत: परिलक्षित होती है। अध्ययन परंपरा के पुनर्जीवन हेतु आप भेंट में शिक्षाप्रद पुस्तकों का चयन खुद करते हैं ताकि यह संदेश समाज में पहुंच सके।

भारतीय दर्शन में चार के अंक का बड़ा महत्व है। फिर चाहे वह हों चार दिशाएं, गृहस्थ आश्रम, वेद या सतयुग से कलियुग तक के कालखंड। शंकराचार्य ने भी वर्षों पूर्व चार धाम की स्थापना की जहां की यात्रा कर आम हिन्दू अपने जीवन को धन्य कर लेता है।

ऐसे में यदि किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार हो जाए जिनके साथ सत्संग में चारों धाम का पुण्य समाया हो तो बात कितनी अद्भुत हो जाती है। तो आइए एक विहंगवालोकन संतश्री सिद्ध भाऊजी के चौमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व का।

1) **स्वाध्याय :** मानस की शुद्धि हेतु स्वाध्याय की महिमा सर्वविदित है। महात्मा गांधी भी स्वाध्याय के सबसे बड़े सूत्रधार थे : जीयो ऐसे जैसे कल मर जाना हो और सीखो ऐसे जैसे आजीवन रहना हो। स्वाध्याय के प्रति भाऊजी की अभिरुचि स्वतः परिलक्षित होती है। अध्ययन परंपरा के पुनर्जीवन हेतु आप भेंट में शिक्षाप्रद पुस्तकों का चयन खुद करते हैं ताकि यह संदेश समाज में पहुंच सके।

2) **सेवा :** सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर केवल वह जो अहंकाररहित हो। सेवा का मन में भाव होना चाहिये। सेवा धर्म सरल भी नहीं। भगवान राम ने खुद कहा है : सेवा धरमु कठिन मैं जाना। इस पैमाने पर संत सिद्ध भाऊजी सेवा के साक्षात अवतार हैं। सुबह से रात्रि के अंतिम पहर तक आप उन्हें स्वार्थ सेवा में व्यस्त पाएंगे। न चेहरे पर कोई थकान या तनाव और न ही मन में कोई गुरूर :

परहित सरिस धरम नहीं भाई
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई

3) **संस्कार:** यह विरासत से प्राप्त वह थाती है जिसका बेटन पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सौंप कर अपने जीवन का सुखद समापन करती है। इसमें गृहण करने योग्य समस्त सूत्र सम्मिलित हैं। ये बालक के जीवन की इमारत में सुदृढ़ नींव का काम करते हैं। इस सत्य को संतजी ने स्वयं के आचरण में अंगीकार करते हुए

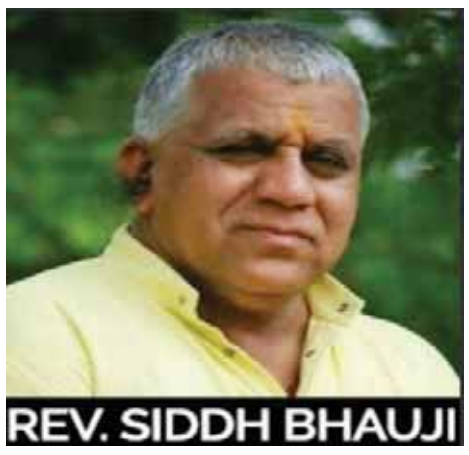

ट्रस्ट सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित करते हुए उन्हें संस्कारधानी में परिवर्तित कर दिया। अध्ययनरत बच्चों तथा बालिकाओं को चरित्रवान बनाते हुए समाज सेवा के पुनीत यज्ञ का सहभागी बनाया है। उसी तरह जैसे राजा राम भोर में उठते ही:

प्रात:काल उठि के रघुनाथा
गुरु पितु मातु नावहिं माथा
आयसू मागि करहिं पुर काजा
देखि चरित हरषइ मन राजा

4) **शिक्षा:** शिक्षा ही कालांतर में बालक को सामर्थ्यवान बनाती है। हिरदाराम ट्रस्ट में इस ध्येय कार्य संपन्न हो पाने का श्रेय आप ही को जाता है। आप जानते हैं कि बालिकाओं के जीवन के सफल संचालन की ठोस नींव तैयार करके ही समाज व देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है
शर्त सिर्फ़ ये है कि सलीके से संवारा जाए

उपरोक्त एक छोटी सी बानगी है माननीय भाऊजी के विनम्र योगदान की। लिखने बैठें तो एक लंबी फेहरिस्त बनती चली जाएगी तकनीकी कौशल, प्राकृतिक चिकित्सा, आरोग्य केन्द्र, निशुल्क शिक्षा से लेकर नेत्र दान आदि तक। शब्द भी एक सीमा तक ही सक्षम हैं। कुछ व्यक्तित्व शब्दों की सीमा से भी परे होते हैं। सो आपको कुछ यूं बयां किया जा सकता है –

सभी चार दिन की है चांदनी, ये तिजारतें, ये वज़ारतें
मुझे उस फकीर की शान दे कि जमाना जिसकी मिसाल दे।

राजा भोज और कुशाभाऊ ठाकरे की ऐतिहासिक धरा को सौगात देने आ रहे जे.पी.नड्डा, मोहन यादव

डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश- विकास और सेवा के 2 वर्ष ' उम्मीद- बदलेगी अंचल की सूरत और सीरत '

धार (राजेश शर्मा)। मंगलवार का प्रभात राजा भोज और कुशाभाऊ ठाकरे की ऐतिहासिक धरा के लिए उम्मीदों का मंगल लेकर आ रहा है। डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश - विकास और सेवा के 2 वर्ष से अंचल और नागरिकों को उम्मीद है कि जिस तरह देश का दिल मध्यप्रदेश डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश पर सवार होकर विकास के नये आयाम गढ रहा है अब अंचल की सूरत और सीरत भी बदलेगी। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन से इस ऐतिहासिक धरा और अंचल के विकास को नए पंख लगेंगे स्वर्णिम सौगात देने आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा और सीएम डॉ. मोहन यादव। केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल सहित विशिष्टजनों की उपस्थिति इस गरिमामय आयोजन के साक्षी बनेंगे। धार को मेडिकल कॉलेज की सौगात से आदिवासी अंचल में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार होगा, साथ ही ला कॉलेज के शुरू होने से धार और जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने की संभावना बढ़ जाएंगी ।

धारेश्वर मंदिर में धारेश्वर लोक का भूमिपूजन सहित 346 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन- ऐतिहासिक नगरी एवं अंचल को सौगात देने आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा , सीएम डॉ. मोहन यादव धारेश्वर मंदिर में धारेश्वर लोक का भूमिपूजन, 15 करोड़ से गीता भवन , 10 करोड़ से माफीपुरा से आमल्या भेरू सड़क निर्माण, 40 करोड़ से तिरला में सी एम राइज स्कूल,धार में ला कालेज, धार तरणताल, 266 करोड़ की लागत से पी पी पी - पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल से मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन सहित 346 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर सौगात देंगे।

डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश - विकास और सेवा के 2 वर्ष से बहेंगी विकास की गंगा- देश का दिल मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश - विकास और सेवा के 2 वर्ष से पश्चिमी मध्यप्रदेश के इस आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी विकास की गंगा तेज़ी से बहेंगी ऐसी उम्मीद डॉ. मोहन यादव से यहां के नागरिकों को है।

जिलेवासियों को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात

380 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का होगा भूमिपूजन और लोकार्पण

बैतूल। बैतूल जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 23 दिसंबर को बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल देगा। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही जिले को विकास की बड़ी सौगात भी मिलेगी। विभिन्न विभागों के अंतर्गत 26.76 करोड़ रुपए की लागत से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा मेडिकल कॉलेज सहित 357.11 करोड़ रुपए की लागत से 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

मिनट - टू - मिनट कार्यक्रम- पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का मंगलवार को दोपहर 2.40 बजे न्यू बैतूल स्कूल कोठी बाजार ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर आगमन होगा। तत्पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 2.45 बजे पुलिस ग्राउंड मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि दोपहर 2.45 से 2.50 तक विभागीय स्टाल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2.50 से 2.55 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मंच पर आगमन, द्वीप प्रज्ज्वलन, माल्यार्पण एवं कन्या पूजन होगा। अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से विधायक हेमंत खंडेलवाल का उद्बोधन तथा केंद्रीय राज्यमंत्री श्री उइके का उद्बोधन होगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन एवं अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण, मेडिकल कॉलेजों पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन होगा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी का उद्बोधन होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी का संबोधन होगा। इसके पश्चात सम्मान समारोह एवं हितलाभ वितरण होगा। इसके बाद म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के द्वारा आभार व्यक्त किए जाने के पश्चात अपराह्न 4-10 बजे मुख्यमंत्री जी का हेलीपेड पर आगमन एवं प्रस्थान होगा।

स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन- पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं भूमि पूजन के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राहियों के आने की संभावना है। उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैतूल डॉ. जगदीश घोरे को संपूर्ण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी एवं प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रांजल उपाध्याय मो.न. को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक से बैतूल के 16 मजदूर पुलिस ने सुरक्षित छुड़ाए

कम मजदूरी और बंधक बनाए गए सात बच्चों सहित सभी लौटे

बैतूल। जिले के बीजादेही थाना क्षेत्र से कर्नाटक में गन्ना कटाई के लिए ले जाए गए 16 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया है। इनमें सात छोटे बच्चे भी शामिल थे। मजदूरों को कम मजदूरी देने और बंधक बनाकर रखने की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। यह मामला तब सामने आया जब रूपलाल मवासे और दिनेश कासदे ने बीजादेही थाने में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि ग्राम फोफ्लिया के कुल 16 मजदूरों को राकेश वंशकार (टिमरनी) और शांरग ठेकेदार (धारणी, महाराष्ट्र) के माध्यम से कर्नाटक के बीजापुर जिले में कल्याण कुमार नामक खेत मालिक के पास गन्ना कटाई के काम पर भेजा गया था। कर्नाटक पहुंचने पर मजदूरों को तय से कम मजदूरी दी जा रही थी। जब उन्होंने वापस लौटने की इच्छा जताई, तो खेत मालिक कल्याण कुमार ने उन्हें रोक लिया और वापस नहीं जाने दिया। शिकायत में यह भी बताया गया कि मजदूरों को वहां भोजन और पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं मिल रही थी। फंसे हुए मजदूरों में शिवनारायण मवासे, श्यामवती, जयनारायण मवासे, सरोता बाई, नामनारायण, कमला, अनिल, ज्ञानसिंह, अनिता सहित सात छोटे बच्चे शामिल थे।

बैतूल एसपी ने बीजापुर एसपी से फोन पर बातचीत की

पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर मामले में समन्वय किया। यह अंतरराज्यीय समन्वय अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, एसडीओपी शाहपुर मयंक तिवारी के नेतृत्व में बीजादेही थाने से एक विशेष पुलिस टीम कर्नाटक के बीजापुर जिले की सिंदगी तहसील भेजी गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम ग्राम कंकड़मेली पहुंची और खेत मालिक से बातचीत कर सभी मजदूरों को सिंदगी थाने लाया गया।

5 पुरूष, 4 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल- कर्नाटक से इन सभी 16 व्यक्तियों (5 पुरुष, 4 महिलाएं और 7 बच्चे) को सुरक्षित वापस लाया गया। उन्हें कंकड़मेली से बस द्वारा कलबुरगी रेलवे स्टेशन ले जाया गया, फिर रेल मार्ग से इटारसी और वहां से बीजादेही थाना लाया गया। बीजादेही पहुंचने पर सभी मजदूरों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तत्परता, अंतरराज्यीय समन्वय और मानवीय संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एसपी-एसडीओपी समेत थाना प्रभारी राजकुमार मीना, एस.आई. जी.पी. बिल्लोरे, प्रधान आरक्षक जगदीश देवड़ा, आरक्षक मिथिलेश उईके और साइबर सेल के आरक्षक बलराम सिंह राजपूत ने सराहनीय भूमिका निभाई।

तीन दिनी राष्ट्रीय गांधी जैविक उत्सव आज से

भोपाल। मध्य भारत में गांधी विचार और दर्शन के सबसे बड़े केंद्र गांधी भवन भोपाल में मंगलवार से तीन दिवसीय राष्ट्रीय गांधी जैविक उत्सव 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उत्सव प्रातः 11 से रात 8 बजे तक आयोजित होगा। भारत में यह पहली बार है जब जैविक उत्सव के प्रतिभागियों को निःशुल्क स्टॉल, आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस उत्सव में लगभग आधा दर्जन राज्यों से कृषि विशेषज्ञ, किसान और स्वयंसेवी संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें पद्मश्री बाबूलाल दहिया, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त और जैविक खेती में नवाचार कर रहे आरके पालीवाल, राष्ट्रीय नीति आयोग की सदस्य और जैविक उत्पादों से आदिवासी महिलाओं को जोड़ रही उपमा दीवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगी।

गांधी भवन के सचिव दयाराम नामदेव ने बताया कि इस तीन दिवसीय उत्सव में जैविक उत्पाद मोटे अनाज, पारंपरिक देशज व्यंजन, हस्तशिल्प एवं जैविक उत्पादों से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विकास संवाद का साहित्य, और बीज के स्टॉल उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गांधी स्मारक निधि के राष्ट्रीय सचिव एवं गांधी भवन भोपाल के अध्यक्ष संजय सिंह , देश के वरिष्ठ पत्रकार व कोषाध्यक्ष राजेश बादल शामिल होंगे। समारोह के अंतिम दिन दयाराम नामदेव जी की पुस्तक 'बीते दिनों की बीती यादें' का लोकार्पण पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा।

सर्व ब्राह्मण युवा संगठन नगर अध्यक्ष पद पर चेतन शर्मा नियुक्त

धार। सर्व ब्राह्मण समाज युवा संगठन धार जिला अध्यक्ष प्रशांत रावल व कार्यकारी अध्यक्ष जितेन्द्र पंड्या ने सर्व ब्राह्मण समाज जिला धार के

जिलाध्यक्ष पं. विश्वास पांडे एवं एवं कार्यकारी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, यात्रा प्रभारी ऋषि भार्गव, वरिष्ठ मार्गदर्शक ज्ञानेंद्र त्रिपाठी व अशोक शास्त्री की अनुशंसा पर लंबे समय से समाज के प्रति मेहनत और निष्ठा के चलते सर्व ब्राह्मण समाज युवा संगठन धार नगर अध्यक्ष पद पर चेतन शर्मा की नियुक्ति की है। आप सर्व ब्राह्मण समाज की मान-सम्मान-प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए समाज हित में नगर की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे व ब्राह्मण समाज के प्रति एकता जागरूकता लाने एवं समाज को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे तथा ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे और समाज को नई मजबूती प्रदान करेंगे ऐसी अपेक्षा की है। श्री शर्मा की नियुक्ति पर सर्व ब्राह्मण समाज धार एवं युवा संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

17 लाख की लागत से होगा ताप्ती सरोवर सुलूश गेट का नवनिर्माण

बैतूल / मुलताई। दो दशक के लंबे इंतजार के बाद ताप्ती सरोवर एवं शनि सरोवर के मध्य स्थित सुलूश गेट का अब नवनिर्माण होने जा रहा है। नगरपालिका द्वारा इसके पुनर्निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। गेट का निर्माण 17 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा तथा ठेकेदार को यह कार्य डेढ़ माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। माना जा रहा है कि वर्षों से खराब पड़े ताप्ती सरोवर सुलूश गेट का नवनिर्माण होने से कुंड से होने वाले जल रिसाव की समस्या समाप्त हो सकेगी और ताप्ती सरोवर का जलस्तर निरंतर बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि गजानन मंदिर के समीप स्थित ताप्ती सरोवर को छोटे तालाब से जोडऩे वाला सुलूश गेट लंबे समय से जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण सरोवर का जल रिसाव होता रहता है और जलस्तर समय से पूर्व घट जाता है। नगरवासी लंबे समय से इसके नवनिर्माण की मांग करते आ रहे हैं। सुलूश गेट के ऊपर बनी पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिया के नीचे लगे लोहे के सरिए उखड़ चुके हैं, जिससे यह वर्षाकाल के दौरान गंभीर संकट का कारण बन सकती है। जागरूक नागरिकों की मांग पर सिंचाई विभाग एवं ओएडम विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार इस पुलिया एवं सुलूश गेट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त गेट को गंभीर स्थिति में बताते हुए इसके पुनर्निर्माण की अनुशंसा की गई थी, किंतु योजना लंबे समय तक परवान नहीं चढ़ सकी। इससे नागरिकों की चिंताएं लगातार बढ़ती रहीं। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अब सुलूश गेट के नवनिर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अनुमान है कि आगामी दो माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया, अनुबंध एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

पहली बार नहीं मिला ठेकेदार, दूसरी बार जारी किया गया टेंडर- मुलताई नगर पालिका ने ताप्ती सरोवर सुलूश गेट निर्माण का एस्टीमेट काफी पहले तैयार कर लिया था। इसमें सिंचाई विभाग के वर्तमान कार्यपालन यंत्री सीएल मरकाम एवं सेवानिवृत्त उपयंत्री सीबी पाटेकर का भी सहयोग लिया गया। उनके मार्गदर्शन में गेट का एस्टीमेट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत 17 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सुलूश गेट के नवनिर्माण की निविदा नगर पालिका द्वारा एक माह पूर्व जारी की गई थी, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके चलते हाल ही में नगर पालिका ने दूसरी बार निविदा आमंत्रित की है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ठेकेदार को यह कार्य 45 दिनों की अवधि में पूरा करना होगा।

धार्मिक आस्था के प्रतीक एवं जल स्त्रोतों के आधार है ताप्ती एवं शनि सरोवर

ताप्ती एवं शनि सरोवर जहां धार्मिक आस्था का केंद्र है, वही मुलताई क्षेत्र के जल स्त्रोतों का आधार भी ताप्ती एवं शनि सरोवर का जलस्तर घटने के साथ ही मुलताई क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में स्थित सभी जल स्त्रोतों का जल स्तर भी घटने लगता है। यही कारण है कि जब वर्षा काल में ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होता है, क्षेत्र में उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि यह पर्याय वर्षा एवं जल स्त्रोतों में वापस जल संग्रह हो जाने का संकेत भी माना जाता है। बीते कुछ वर्षों से ताप्ती सरोवर का जल स्तर अपेक्षाकृत तेजी से घट रहा है। जिसके रोकथाम के लिए सुलूश गेट का नव निर्माण प्रथम कदम है किंतु इसके साथ ही सरोवर के अन्य स्त्रोतों को भी सुधारा जाना चाहिए।

इनका कहना है -

ताप्ती सरोवर सुलूश गेट का नवनिर्माण 17 लाख रुपये की लागत से किया जाना है। पहली बार ठेकेदारों द्वारा भाग न लेने के कारण नगर पालिका ने दूसरी बार निविदा आमंत्रित की है।

- महेश शर्मा,
उपयंत्री, नगर पालिका मुलताई

कुएं के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, 6 घायल

बैतूल। बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम मधनी आमढाना में पुश्तैनी कुएं के उपयोग को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में चाचा और भतीजे के परिवारों के बीच हुए हमले में एक बुजुर्ग सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, एक ही परिवार के चाचा और भतीजे के बीच कुएं को बंद करने और उसके उपयोग को लेकर शनिवार से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने बोरदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत कर थाने से लौटते समय, रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 10 से 15 लोगों ने अचानक परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के लाठी, डंडे, रॉड और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में 70 वर्षीय किशन अमरूते गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य घायलों में हिमांशु अमरूते (19), संजय अमरूते (35), राजेश अमरूते (40), संगीता अमरूते (36) और जयश्री अमरूते (18) शामिल हैं। सभी घायलों को पहले बोरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर उन्हें बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया गया। देर रात करीब 11.30 बजे उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। बोरदेही थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे के सीनियर डीसीएम ने माना जीएम आते हैं तब करना पड़ता है कई योजनाओं पर काम

रेलवे सुरक्षा दीवार होने के बावजूद अलग से फेंसिंग बनाने के मामले में जांच का आश्वासन

आमला। 24 दिसंबर को रेलवे के जनरल मैनेजर वी.गुप्ता आमला का दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर बीते एक माह से रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी सहित पूरे रेल परिसर को विशेष रूप से सुसज्जित किया जा रहा है। रेलवे के जीएम के दौरे को लेकर नागपुर डिवीजन के डीआरएम विनायक गर्ग ने सोमवार को रेलवे परिक्षेत्र की उन सभी इलाकों का भी दौरा किया, जहां-जहां रेलवे के जनरल मैनेजर जाने वाले हैं, जिनमें आमला रेलवे स्टेशन, ड्राइवर

गार्ड लॉबी,रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे कॉलोनी और निर्माणाधीन रेलवे की नई कार्यालय बिल्डिंग शामिल है। आमला रेलवे में जनरल मैनेजर के दौरे पर रेलवे में किया जा रहे अनावश्यक खर्च को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में सीनियर डीसीएम ने माना है कि जब भी रेलवे के जनरल मैनेजर आते हैं, तो पूरे स्टेशन परिसर का खास तौर पर रंग रोगन और सुधार कार्य किया जाता है, ये अनावश्यक खर्च नहीं है, किंतु जब मीडिया ने ये सवाल किया कि यहां ऐसे स्थल जहां अभी अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों के कार्य चल रहे है, जिनमें कुछ जगह मसलन पुराना रेलवे ब्रिज, बुकिंग ऑफिस भी तोड़ा जाना है, उन स्थलों पर भी आखिर खर्चा क्यों किया जा रहा है। जिस पर सीनियर डीसीएम अमन मित्तल ने कहा कि उपरोक्त स्थल अभी लगभग एक वर्ष तक ऐसे ही रहने वाले हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए ही यह खर्च किया जा रहा है। मीडिया के एक सवाल, जिसमें पूछा गया कि वार्ड नंबर 5 और 6 से लगी रेलवे सीमा पर जहां पहले से ही रेलवे की सुरक्षा दीवार बनी हुई है, वहां भी रेलवे अपने आप को समेटते हुए नई फेसिंग कर रही है, इस सवाल के जवाब में सीनियर डीसीएम ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी।

अनुशासन-नेतृत्व क्षमता के साथ स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण : सावित्री ठाकुर

सांसद खेल महोत्सव का धार में हुआ समापन, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, डॉ. कविता पाटीदार सहित विशिष्ट जन उपस्थित हुए

धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप एवं क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के अपने साकार करने एवं खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूम्बर से 25 दिसम्बर 2025 के मध्य किया जाना था। सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन उदय रंजन खेल मैदान में आयोजित किया गया। सांसद खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ सुमेरसिंह सोलंकी,कार्यक्रम संयोजक केंद्रीय राज्यमंत्री क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर राज्यसभा सांसद डॉ कविता पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, विधायक नीना वर्मा समेत प्रशासनिक अधिकारी खेल अधिकारी एवं कर्मचारी मंचासीन रहे। अतिथि डॉ सुमेर सिंह सोलंकी और डॉ कविता पाटीदार ने पीएम के खेलो इंडिया, फिट इंडिया अभियान को गति देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली स्पर्धाओं में खेल भावना और कौशल दिखाने पर खिलाड़ियों की प्रशंसा की।

कार्यक्रम संयोजक व क्षेत्रीय सांसद केन्द्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि खेलों से अनुशासन

आता है। नेतृत्व क्षमता और समन्वय जैसी कलाओं का विकास होता है। खेल सिर्फ प्रतियोगिताएं ही नहीं बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया मुवमेंट की संकल्पना की गई है। इसी को साकार करने के उद्देश्य से खेल महोत्सव सहित अन्य गतिविधियां आयोजित हो रही है।

जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्पर्धाओं और जिला स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सम्मानित- सांसद खेल महोतसव के तहत जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही थी। विधानसभा स्तर पर गतिविधियों के पश्चात चयनित खिलाड़ियों को लोकसभा स्तरीय स्पर्धाओं में प्रदर्शन का अवसर मिला। समापन अवसर पर रविवार को अलग-अलग खेल मैदानों और प्रशिक्षण संस्थाओं में कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबाल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलैटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई। जिसमें शासकीय विद्यालयों के खिलाड़ी विद्यार्थी सहित अन्य संस्थाओं के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। समापन अवसर पर अतिथियों द्वारा स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों से मंच से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया की सांसद खेल महोत्सव समापन के अवसर पर पूर्व सांसद छतरसिंह दरबार,पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी, जिला महामंत्री राकेश पटेल, देवेंद्र सोनोने ,पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया ,मुकाम सिंह निगवाल, भाजपा नेता शेखर यादव नव नियुक्त जिला पदाधिकारी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

रीवा-इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ

इंदौर तक हवाई सेवा से विन्ध्यवासियों को बड़े शहरों से जुड़ने की सुविधा मिली है : शुक्ल

भोपाल (नप्र)। रीवा एयरपोर्ट की स्थापना के बाद विन्ध्य में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा से इंदौर के लिए इंडिगो की 72 सीटर हवाई जहाज की सुविधा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विन्ध्यवासियों

- **नई हवाई सेवा विन्ध्य को सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केन्द्र से जोड़ेगी – मंत्री विजयवर्गीय**
- **उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के जिद और जुनून ने रीवा को विकास के नए आयाम दिए**

का आज वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। इंदौर तक हवाई सेवा की सुविधा से विन्ध्यवासी कई बड़े शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे। देश ही नहीं कई विदेश के शहरों के लिए भी अब जाना सुगम हो गया है। यह हवाई सेवा क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और उद्योगों के विकास को गति देगी। विन्ध्य में मनोरम जलप्रपात, सुंदर वन और टाइगर रिजर्व, कई प्रसिद्ध मंदिर, सीमेंट और थर्मल पावर के बड़े कारखाने स्थित हैं। हवाई सेवा की सुविधा से विन्ध्य में तेजी से विकास होगा।

उन्होंने कहा कि रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा श्री शिवराज सिंह चौहान एवं विन्ध्य के सांसदों ने सराहनीय योगदान दिया।

समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज केवल एक फ्लाइट नहीं आई है। आज विन्ध्य के लिए विकास की सौगात आई है। हवाई सेवा के माध्यम से रीवा और विन्ध्य क्षेत्र सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केन्द्र और मध्यप्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से जुड़ गया है। इससे दोनों क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार के विकास को गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल सही मायनों में विन्ध्य के विकास पुरूष हैं। उनके के जिद और जुनून ने विन्ध्य के विकास को नए आयाम दिए हैं। इस हवाई सेवा ने उज्जैन के महाकाल भगवान और मैहर की माँ शारदा के स्थलों को जोड़ दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से बाणसागर बांध का पानी विन्ध्य के जिन क्षेत्रों में पहुंचा वहाँ पर धरती सोना उगलने लगी। यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति तेजी से बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल और उनकी टीम के लगातार प्रयासों से पिछले 15 वर्षों में रीवा की तस्वीर बदल गई है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने हवाई सेवा देने वाली इंडिगो के अधिकारियों से किराये को लिमिट में रखने और हवाई सेवा के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि आज से विन्ध्य के विकास को पंख लग गए हैं। लगातार प्रयासों को आज सफलता मिली है। सांसद सतना श्री गणेश सिंह ने कहा कि इंदौर तक हवाई सेवा की सुविधा मिलने से विन्ध्य क्षेत्र देश के बड़े शहरों से सीधे जुड़ गया है। पिछले दो वर्षों में पूरे प्रदेश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। एयर एंबुलेंस और हेली सेवा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सांसद सीधी डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि आज से रीवा का ग्लोबनाइजेशन हो गया है। अब दो दिन की यात्रा दो घंटे में पूरी हो रही है। समारोह में विधायक मैहर श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल, विधायक मनगवां श्री नरेन्द्र प्रजापति, विधायक गुढ़ श्री नागेन्द्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत इंडिगो एयरवेज के वाइस प्रेसिडेंट वरूण द्विवेदी ने किया। समारोह में लोक गायिका राखी द्विवेदी ने मनोहारी लोकगीत गाए। इंदौर से प्रथम फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों का रीवा में भव्य स्वागत किया गया। राम दरबार सामाजिक संस्था के सदस्यों ने पुष्पवर्षा और वैदिक मंत्रों से यात्रियों का स्वागत किया। समारोह में विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह, विधायक चित्रकूट सुरेन्द्र सिंह गहरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम श्री व्यंकटेश पाण्डेय, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।

भोपाल मेट्रो में थूकने पर जुर्माना...

पेट्स के साथ सफर नहीं कर सकेंगे ; बिना वजह इमरजेंसी बटन दबाया तो 10 हजार देने होंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल मेट्रो में यात्री अपने पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे। शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति जरूर मिल सकती है, लेकिन शर्त रहेगी कि बोतल सीलबंद हो। यात्री अपने साथ पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते।

मोबाइल या स्मार्ट वॉच की परमिशन है लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और रेडियो संचार उपकरण, कैमरा ले जाने की मनाही है। संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से परेशान और असंयमी, शराबी पैसेंजर सफर नहीं कर सकेगा। विमान की तरह ही इसमें सामान का वजन भी तय है। मेट्रो में आप अधिकतम 25 किलो वजनी सामान ही ले जा सकते हैं।

घोषणा के करीब 7 साल बाद भोपाल मेट्रो ट्रेन वाला देश का 26वां शहर बना है। रविवार को पहले दिन मेट्रो में करीब 6 हजार लोगों ने सफर किया। इस दौरान उन्हें कई पाबंदियों से भी गुजरना पड़ा। ऐसे में मेट्रो के यात्रियों को कई बातों का ख्याल रखने की जरूरत है ताकि उनके सफर में कोई रुकावट न हो।

ये खेल उपकरण पैक कर ले जा सकेंगे- मेट्रो में सफर करने वाले यात्री तीरंदाजी, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी या नानचाकू जैसे खेल उपकरण सक्रिय खिलाड़ी या संचालक की अनुमति से ढककर या पैक कर ले जा सकते हैं।

सभी 8 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर- भोपाल में मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक है। इस दौरान कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स हैं। इन सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो यात्रियों पर नजर रखे हुए हैं। मेट्रो ट्रेन में भी सीसीटीवी सर्विलांस है। हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी कंपनी के ढाई सौ गार्ड भी तैनात किए गए हैं। पहले और दूसरे दिन कुछ यात्रियों ने गार्ड्स के गलत व्यवहार की शिकायत भी मेट्रो अफसरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है।

बेवजह इमरजेंसी बटन दबाया तो 10 हजार का जुर्माना- यदि आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं और बेवजह इमरजेंसी बटन दबा दिया तो आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। मेट्रो अफसरों के अनुसार, ऐसे अलग-अलग मामलों में 200 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो के अंदर या स्टेशन पर थूकने पर 200 रुपए लगेंगे। बिना टिकट यात्रा करने पर सभी स्टेशनों पर लगने वाले किराए समेत 50 रुपए अलग से देने होंगे।

यात्री मेट्रो स्टेशन या गाड़ी के अंदर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोच में तोड़फोड़, कुछ लिखने या चस्पा करने, कोच छोड़ने से मना करने, आपत्तिजनक सामग्री ले जाने, अनधिकृत तरीके से कोई सामान बेचने की परमिशन भी नहीं है।

इनके उल्लंघन पर मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम 2002 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान भी है। सभी 8 मेट्रो स्टेशनों पर इसकी जानकारी भी दी गई है।

भोपाल में महिला पटवारी की छत से गिरकर मौत

बेटी का बैलून उतारते समय फिसला था पैर, शेड की चादरें तोड़कर पड़ोसी के घर में गिरीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कमला नगर इलाके में रहने वाली एक महिला पटवारी की छत से गिरकर मौत हो गई। बच्ची का बैलून उतारने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे शेड की चादरों सहित पड़ोसी के घर में जा गिरीं। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई।

मीनाक्षी पटेल, मृतक

पुलिस के मुताबिक मृतका 32 वर्षीय मीनाक्षी पटेल रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ थीं। उनके पति सेना में कार्यरत हैं, जबकि ससुर पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। घटना 11 दिसंबर की शाम की है, जब मीनाक्षी अपनी बच्ची के साथ छत पर खेल रही थीं।

शेड की चादरें तोड़ते हुए गिर पड़ीं- परिजनों ने बताया कि खेलते समय बच्ची का बैलून पड़ोसी के शेड पर गिर गया। बैलून उतारने के प्रयास में मीनाक्षी बालकनी की बाउंड्री पार कर शेड पर उतरने लगीं। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे शेड की चादरें तोड़ते हुए नीचे पड़ोसी के घर में गिर पड़ीं।जीएमसी की मर्चुरी में सोमवार दोपहर पीएम के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

डॉक्टर बोले- सिर में खून जम गया था- हादसे के बाद परिजन उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगने से अंदर खून जम गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महान गणितज्ञ श्री रामानुजन की जयंती पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर उन्हें नमन किया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैदिक काल से देश के महान गणितज्ञों, विद्वानों ने गणित को परिष्कृत किया और विश्व को इस महान विद्या से परिचित भी कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय गणित दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। उल्लेखनीय है कि गणितज्ञ श्री रामानुजन की जयंती, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप मे मनाई जाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल से सौजन्य मुलाकात की।

एम्स भोपाल में जरूरी जांचें बंद, इलाज अटका

भर्ती मरीज सबसे ज्यादा परेशान, डॉक्टरों को बाहर से जांच ना कराने के निर्देश, अंदर सुविधा नहीं

भोपाल (नप्र)। देश के सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य संस्थानों में गिने जाने वाले एम्स भोपाल में इन दिनों मरीज इलाज से पहले ही परेशान हो रहे हैं। वजह है कई बेहद जरूरी जांचों का बंद होना। हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर जांच लिख रहे हैं, लेकिन लैब से मरीजों को सीधा जवाब मिल रहा है कि यह जांच फिलहाल बंद है। ब्लड कल्चर, यूरीन कल्चर, हेपेटाइटिस-सी, एएसओ टेस्ट, आरएच फैक्टर, आरएस फैक्टर और एच1-बीएसी जैसी जांचें उपलब्ध न होने से इलाज की पूरी प्रक्रिया लड़खड़ा गई है।

जिससे रोजाना एम्स में आने वाले 3 हजार से ज्यादा मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो अस्पताल में भर्ती हैं।

दरअसल, भर्ती मरीजों की जांच बाहर से कराने पर रोक है। ऐसे में डॉक्टर सर्जरी से पहले उनकी जांच बहार से नहीं करा पा रहे हैं। वहीं, अंदर सुविधा ही नहीं हैं। इन मरीजों में सबसे बड़ी संख्या गर्भवती महिलाओं, किडनी और लिवर मरीजों के साथ इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की है।

ओपीडी में आने वाले मरीज निजी लैब के भरोसे- एम्स के बाहर कई बड़े-बड़े निजी सेंटर खुले हुए हैं। जहां ब्रॉन्डिंग इस तरह की जा रही है, जैसे वो एम्स का ही हिस्सा हो। हालांकि, एम्स में जांच ना होने से ओपीडी में आने वाले मरीजों को मजबूरन इन्हीं सेंटर में महंगी जांच करानी पड़ रही है।

एम्स भोपाल में ओपीडी मरीजों और कम गंभीर मरीजों को सिटी स्कैन और एमआरआई जांच के लिए 3 से 6 माह बाद की डेट दी जा रही है।

गजब! महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

डॉक्टर भी हैरान, 7 लाख में एकाध बार होता है ऐसा चमत्कार

छिंदवाड़ा (नप्र)। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के बरेलीपार गांव में एक अत्यंत दुर्लभ चिकित्सकीय मामला सामने आया है। यहां 28 वर्षीय महिला कुन्नू इवनाती ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। प्रसूता ने एक बेटे और तीन बेटियों को जन्म दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार, रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर महिला को परिजन तत्काल जुन्नारदेव सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला की हालत और संभावित जटिलता को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष तैयारी के साथ प्रसव कराया। चिकित्सकीय टीम की सतर्कता और कुशल प्रबंधन के चलते प्रसव सफल रहा। चार बच्चों के एक साथ जन्म लेने की सूचना मिलते ही अस्पताल में हलचल मच गई।

चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मल्टीपल बर्थ में नवजातों को श्वसन, तापमान और पोषण से जुड़ी जटिलताओं का खतरा अधिक रहता है।

नवजात बेटियां स्वस्थ, नवजात बेटे की हालत नाजुक- प्रसव के बाद नवजातों की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि तीनों बच्चियों की स्थिति संतोषजनक है, जबकि नवजात बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके बाद डॉक्टरों ने बिना देरी किए बेहतर इलाज के लिए चारों बच्चों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर कर दिया।

परिवार में खुशी के साथ चिंता पहले ऐसा कभी नहीं देखा

चार बच्चों के जन्म से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है, लेकिन नवजात बेटे की नाजुक हालत को लेकर परिजनों में चिंता भी बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा था और वे चिकित्सकों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं।

दुर्लभ केस , 7 लाख में एक मामला

मेडिकल साइंस में चार बच्चों के एक साथ जन्म लेने को बेहद दुर्लभ माना जाता है। दो ओर तीन बच्चों के मामले में अक्सर सामने बाते रहते हैं, लेकिन एक साथ चार बच्चों का जन्म रेयर होता है। मेडिकल जर्नल के मुताबिक करीब 7 लाख प्रसव के केस में ऐसा एकाध मामला सामने आता है।

भोपाल के अयोध्या बायपास पर 81 हजार पौधे रोपेगा एनएचएआई

2075 पेड़ों के लिए बदला प्लान सेंट्रल वर्ज 1.5 मीटर की रहेगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के आसाराम चौराहा से रत्नागिरि तिराहे तक 16 किमी लंबे अयोध्या बायपास में जिन पेड़ों को काटा जाएगा, उसके बदले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) 81 हजार पौधे रोपेगा। दूसरी ओर, 10 लेन करने के प्रोजेक्ट में सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई को 5 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर किया जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ उस इलाके में होगा, जहां हरियाली है। ऐसा करने से 2075 पेड़ बचेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रूबनल (एनजीटी) के निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी के निर्देश के बाद एनएचएआई ने अपना प्लान बदला है। दूसरी ओर, वह 10 लेन सड़क में करीब 10 लाख टन सूटेबल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए भोपाल नगर निगम से डिमांड भी की गई है।

इन जगहों पर लगेंगे पौधे- दस लेन सड़क बनाने के बदले कुल 7871 पेड़ कटेंगे। उनके एवज में एनएचएआई कुल 81 हजार पौधे लगाएगा। 10 हजार पौधे अयोध्या बायपास के दोनों ओर लगेंगे। इनमें छाया, फलदार एवं शेड-बेयरिंग प्रजाति के पौधे शामिल हैं। इन पौधों की 15 साल एनएचएआई देखरेख करेगा। करीब 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस संबंध में केंद्रीय अधिकार समिति को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। नगर निगम के सहयोग से 10 हजार अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जाएगा। नगर निगम ने एनएचएआई को विभिन्न पार्क, रिक्त भूमि एवं सड़क किनारे की उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई है।

सियासी 'करीबियों' की बायोडाटा डिप्लोमेसी

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी क्या हुई, मध्य प्रदेश भाजपा के युवा तुर्कों में अचानक 'स्मृति-पुनरुद्धार' का ऐतिहासिक दौरा पड़ गया है। कल तक जो नेता सामान्य परिचय को तरसते थे, आज वे अपनी फाइलों से वो प्राचीन सूचियाँ खोदकर निकाल रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष जी के साथ उनका नाम 'महासचिव' की पंक्ति में बगल-बगल छपा था। यह होड़ महज पद की नहीं, बल्कि 'वफादारी के पुराने सबूत' पेश करने की है। एक नेताजी ने तो बाकायदा युवा मोर्चा के जमाने का वो पीला पड़ चुका कागज सार्वजनिक कर दिया है, मानो यह साबित करना चाह रहे हों कि जब अध्यक्ष जी पहला कदम बढ़ा रहे थे, तो कदमताल की आवाज उनकी ही थी। राजनीति का यह अद्भुत रंग है—यहाँ वर्तमान की चमक पाने के लिए अतीत के दफन दस्तावेजों को ऐसे पेश किया जा रहा है, जैसे कोई अपनी वंशावली सिद्ध कर रहा हो। अब देखना यह है कि ये पुराने 'महासचिव' वाले कनेक्शन, नए 'कार्यकारी' दौर में कितने प्रमोशन की सिफारिश बन पाते हैं या फिर यह सूची महज सोशल मीडिया की एक 'थ्रोबैक फोटो' बनकर रह जाती है!

'अंतरराष्ट्रीय खतरा' बन गए

गजब की फुर्ती है साहब! कल तक जो मंत्री जी अपने सरकारी बंगले के बगीचे में 'अतिथि देवो भवः' का जाप कर रहे थे, आज वहां सुरक्षा की दीवारें आसमान छूने लगी हैं। लुटियंस की गलियों में चर्चा है कि मंत्री जी ने खुद दिल्ली दरबार में जाकर गुहार लगाई कि उनकी 'साख' और 'सुरक्षा' दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। असली किस्सा तो ये है कि पिछले दिनों विपक्षी दल के कुछ नेता उनके आंगन तक क्या पहुँच गए, मंत्री जी को अपना घर 'हल्दीघाटी का मैदान' लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान चाय पर आते रहे, तो उनके निजी सुकून का 'राम नाम सत्य' हो जाएगा। अब विडंबना देखिए, अपनी 'निजी चिंता' को 'राष्ट्रीय चिंता' का जामा पहनाने के लिए तुरंत ISI और अंतरराष्ट्रीय साजिशों का तड़का लगा दिया गया। सूत्रों की मानें तो मंत्री जी ने निवेदन ऐसे किया जैसे सरहद पर टैंक तैनात करने हों, और दुनिया को बताया गया कि खतरा 'सात समंदर पार' से है। सच तो ये है कि डर सीमा पार वाले दुश्मनों का नहीं, बल्कि पड़ोस वाले 'विपक्षियों' का था जो बिना अपॉइंटमेंट के ड्राइंग रूम तक पहुँचने की जुर्रत कर बैठे थे। इसे कहते हैं– 'डर घर का और इल्जाम सरहद पार का!'

साहिबों की महफिल और 'मेट्रो' की रफ्तार

इस साल आईएएस अफसरों की वार्षिक 'मीट' कुछ वैसी ही रही जैसे बिना नमक के शाही पकवान—दिखने में भव्य, पर स्वाद नदारद। आमतौर पर जिस आयोजन में सत्ता की धमक और अफसरों की खनक गूँजती थी, इस बार वहाँ 'शांति' का राज रहा। वजह भी वाजिब थी; एसआईआर के चलते जूनियर साहबों ने जिलों की मोह-माया छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें लगा कि राजधानी में डिनर करने से बेहतर है जिले में रहकर 'साहब' बने रहना, आखिर 'ग्राउंड जीरो' की धूल में जो रसूख है, वह वातानुकूलित मीटिंग हॉल में कहाँ! रही-सही कसर सरकार की दो साल की उपलब्धियों और 'मेट्रो' की रफ़्तार ने पूरी कर दी। अखबारों के पन्ने मेट्रो की चमक और सरकार के कसीदों से इतने भरे थे कि अफसरों की इस 'पारिवारिक' मीट को कोने में भी जगह बड़ी मुश्किल से मिली। जब शहर की पटरियों पर मेट्रो दौड़ रही हो और विज्ञापनों में सरकार मुस्कुरा रही हो, तो भला चंद अफसरों के आपसी मेल-मिलाप को कौन 'प्राइम टाइम' दे? आलम यह था कि साहब लोग सूट-बूट पहनकर एक-दूसरे का चेहरा देखते रहे और सुर्खियां कोई और बटोर ले गया। इसे कहते हैं–'ब्यूरोक्रेसी' के अपने ही घर में मेहमान बन जाना!

भाजपा के हुये मान!

'कल तक जो 'पूर्व आईएएस साहब' दिग्विजय सरकार के दौर में कांग्रेसी विचारधारा के प्रमुख वक्ता हुआ करते थे। अचानक पुरानी विचारधारा को बिसरा कर भाजपा की 'विचारधारा' का प्रचार करते सुनाई दे रहे हैं। इसे सत्ता का मोह कहें या वक्त का तकाज़ा, पर रिटायरमेंट के बाद का यह 'मोक्ष' वाकई अद्भुत है। कल तक जिनके लहजे में गांधीवादी दर्शन की चाशनी घुली थी, आज उनके सुरों में अचानक 'राष्ट्रवाद' की प्रखर गूँज सुनाई देने लगी है। खादी के पुराने थान से निकलकर केसरिया दुपट्टे तक का यह सफर इतना खामोश रहा कि खुद स्याही को भी नहीं पता चला कि कब उसका रंग बदल गया। सच है, साहब ने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए 'पब्लिक सर्वेंट' की भूमिका इतनी ईमानदारी से निभाई कि अब वे जनसेवा के नाम पर 'पावर' के सबसे करीब वाले केंद्र की सेवा में हाजिर हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल तक जो फाइलें 'पंजे' की मजबूती के लिए दौड़ती थीं, वे अब 'कमल' को खिलाने के लिए कौन सा नया खाद-पानी तैयार करती हैं!'

सांसद जी को 'विधायक' बनने का शौक चढ़ा!

देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में बैठकर तकरीरें देने के बाद, अब हमारे माननीय सांसद जी का मन 'दिल्ली की गलियों' से भर गया है। सुना है कि जब से भाजपा के युवा कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, तब से माननीय की अपेक्षाओं ने ऐसी कुलांचे भरी हैं कि वे अब वापस मध्य प्रदेश की सड़कों पर 'विधायक' बनकर धूल छानने को बेताब हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पीएचडी धारक व्यक्ति यह कहकर स्कूल में दाखिला मांगे कि उसे 'क' 'ख' 'ग' फिर से पढ़ना है। अखबार नवीसों के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर उन्होंने यह तो साफ कर दिया कि राजनीति में 'प्रमोशन' और 'डिमोशन' की परिभाषा सिर्फ कुर्सी की दूरी से तय होती है। दिल्ली का रसूख अपनी जगह, पर असली मजा तो भोपाल की विधानसभा की कैंटीन और क्षेत्र की गलियों में 'माननीय विधायक जी' कहलाने में ही है। शायद सांसद जी को लगता है कि दिल्ली दूर है और भोपाल का रास्ता उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए ज्यादा 'शॉर्टकट' साबित होगा। खैर, लोकतंत्र का यही तो हुस्न है–ऊपर चढ़कर नीचे उतरने की ऐसी ललक सिर्फ राजनीति के खिलाड़ियों में ही दिखती है!

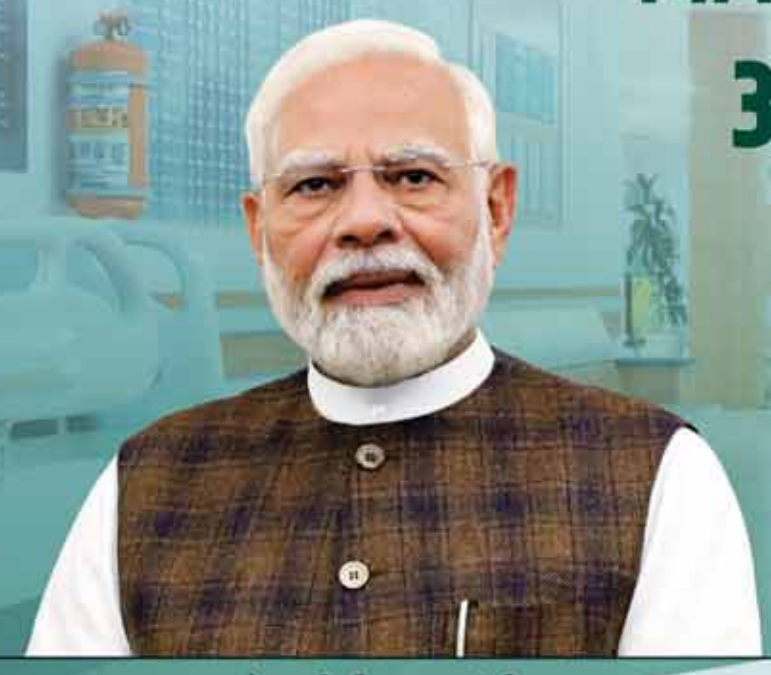

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में
अग्रणी मध्यप्रदेश
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
'जन-निजी भागीदारी आधारित'
धार और बैतूल
चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास
विकास कार्यों का भूमिपूजन
और लोकार्पण
मुख्य अतिथि
जे. पी. नड्डा
केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
अध्यक्षता
डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
23 दिसम्बर, 2025
पूर्वाह्न 11:00 बजे । पीजी कॉलेज ग्राउंड, जिला धार
अपराह्न 2:00 बजे । पुलिस ग्राउंड, जिला बैतूल
डॉ. मोहन यादव का
अभ्युदय मध्यप्रदेश
पिछले 2 वर्ष में तेजी से
बेहतर हुईं स्वास्थ्य सेवाएं
सुदृढ़ होती चिकित्सा शिक्षा
• शासकीय मेडिकल कॉलेज 14 से 19, निजी 12 से बढ़कर 14 हुए
• शासकीय एमबीबीएस सीटें 2275 से 2850 एवं शासकीय पीजी सीटें 1262 से 1468 हुईं
• शासकीय सुपर-स्पेशलिटी सीटें 47 से 64 हुईं
अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण
• मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा में तीन नए जिला चिकित्सालयों का निर्माण
• इंदौर, रीवा, सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन
उन्नत चिकित्सा सेवाएं
• भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर में सीटी/एमआरआई मशीनें
• इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर मशीनें
• भोपाल, रीवा में कैथ लैब
• इंदौर, जबलपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट
• इंदौर में कार-टी सेल थैरेपी
जनहितकारी सेवाएं
• पीएमश्री एयर एम्बुलेंस, 109 मरीज एयरलिफ्ट
• 1268 दूरस्थ ग्रामों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट
• सीएम डे-केयर सेंटर
विकास और सेवा के 2 वर्ष
सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-11170/25
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025